तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.taruchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
phone: 0771-2543112

■ रायपुर,बुधवार 1 जुलाई 2026 ■ आषाढ़, कृष्ण पक्ष-1/2 ■ वर्ष -42 ■ अंक-094 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 02 जुलाई 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ

नई दिल्ली,1 जुलाई। जुलाई महीने का पहला दिन लोगों के लिए खुशखबरी और राहत देने वाला रहा। एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल भी सस्ता हो गया है। पेट्रोल 5 और डीजल 3 सस्ता हुआ है। ये कटौती नायरा एनर्जी ने की है। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। नई कीमतें आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। नयारा एनर्जी के बाद इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम भी तेल के दाम सस्ता कर सकता है। बता दें कि इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 180 रुपये की कटौती की है।

कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग

कोरबा,1 जुलाई। शहर के पावर हाउस रोड स्थित पैसा वसूल क्लॉथ स्टोर में मंगलवार को देर रात भीषण आग लग गई. दुकानें से आग की लपटें और धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण अधिकांश बाजार बंद था। देर रात करीब 12 बजे स्थानीय लोगों ने पैसा वसूल क्लॉथ स्टोर से धुआं निकलते देखा। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दुकान मालिक भी मौके पर पहुंच गया. दुकान बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई. आग ने पूरी दूकान को चपेट में ले लिया था. सारा सामान जलकर खाक चुका था. दमकल विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग समय रहते काबू में आ गई, जिससे वह बगल की दुकानों तक नहीं फैल पाई। फिलहाल आग कैसे लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. दुकान संचालक के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. वहीं मामले की जांच जारी है.

रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जारी

नई दिल्ली,1 जुलाई। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थी अपने रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थी अपने रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं।

गंदे पानी से किया ब्रश, सड़क में ही साबुन लगाकर नहाया

जर्जर सड़क: सरकार के खिलाफ ग्रामीण का अनोखा विरोध प्रदर्शन

जांजगीर-चांपा,1 जुलाई। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोंगाकोहरौद से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पिछले कई वर्षों से पक्की सड़क की मांग कर रहे स्थानीय ग्रामीणों का सब्र अब टूट चुका है। अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने सोमवार से आमरण अनशन शुरू किया था, जिसने अब एक बेहद संवेदनशील और अनोखे प्रदर्शन का रूप ले लिया है। बीती रात हुई भारी बारिश के कारण जब जर्जर सड़क पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गई, तो एक आंदोलनकारी ग्रामीण ने बीच सड़क पर जमा हुए उसी गंदे और दूषित पानी से ब्रश किया और साबुन लगाकर स्नान किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे की बदहाली और शासन-प्रशासन की कथित संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। डोंगाकोहरौद के ग्रामीण केवल खोखले आश्वासनों से तंग आकर अब धरातल पर ठोस काम शुरू होने तक अन्न-जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं और दूषित पानी से ब्रश किया और साबुन लगाकर स्नान किया। इस घटना का तबीयत अचानक खराब हो गई, जिन्हें आनन-फानन में पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आंदोलन के तीसरे दिन भी स्थानीय प्रशासन या लोक निर्माण विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी स्थिति का जायजा लेने या ग्रामीणों को मनाने नहीं पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश ने लगातार दूसरे दिन अनशन स्थल पहुंचकर ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण सीजन में किसानों को अपने खेत छोड़कर सड़क पर बैठना पड़ रहा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

हनीट्रैप : ब्लैकमेल कर ऐंठ लिए लाखों रुपये

रायपुर,1 जुलाई। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला और उसकी एक सहयोगी के खिलाफ अश्लील तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ब्रता दें कि बीरगांव के गांधी नगर निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी पहचान अशोक नगर श्मशान घाट के पास रहने वाली एक महिला से थी. शिकायत के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को महिला के बुलावे पर वह उसके घर गया था, जहां पहले से एक अन्य महिला भी मौजूद थी। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने उसे जबरन शराब पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसके बाद वह बेहोश हो गया। पीड़ित का कहना है कि होश आने पर उसने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया और उसके अश्लील फोटो खींचे जा चुके थे। इसके बाद दो दिन बाद आरोपित महिला ने उसे फिर अपने घर बुलाया और कथित तौर पर दूसरी महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं। इन तस्वीरों को परिवार और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग की गई। डर और सामाजिक बदनामी के कारण पीड़ित ने आरोपितों के दबाव में आकर भुगतान करना शुरू कर दिया।

तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा

काबूल,1 जुलाई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने बड़ा पलटवार करते हुए मंगलवार रात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमला किया। तालिबान के ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का एक स्कूल भी शामिल है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि पाकिस्तान ने 29 जून की रात अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में एयरस्ट्राइक की की थी। पाकिस्तान के कायराना हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसका बदला लेने का ऐलान किया था। ऐलान के 24 घंटे के अंदर 30 जून की रात 11 बजे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में जवाबी ड्रोन हमला किया।

तालिबान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। तालिबान ने दावा किया कि उनके निशाने पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान (आईएसआईएस-के) के अड्डे थे। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल 'टोलो न्यूज' ने भी इस दावे की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान के ड्रोन विमानों ने सीधे उन ठिकानों को हिट किया जहां आईएसआईएस-के के आतंकी छिपे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरान इलाके में तो एक स्कूल को मलबे में तब्दील कर दिया। तालिबान के मुताबिक इस हमले में कई आतंकी ढेर हुए हैं। इधर पाकिस्तान रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये स्ट्राइक जिस इमारत पर हुई थी, वो असल में एक स्कूल था। वहां पर अफगान सेना के पूर्व सैनिक रहते थे और अफगान सेना के हमले में 3 पूर्व सैनिक घायल हुए हैं।

मनरेगा की जगह आज से वीबी-जी राम जी लागू

100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी, दिहाड़ी भी बढ़ा

नई दिल्ली,1 जुलाई। मनरेगा की जगह आया वीबी-जी राम जीः ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना 'मनरेगा' आज से इतिहास से पन्नों में दर्ज हो गया। केंद्र की मोदी सरकार आज से मनरेगा की जगह नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 यानी वीबी-जी राम-जी कानून (वीबी-जी राम जी) लागू कर दिया है। वीबी-जी राम जी के तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वहीं, देशभर में औसत दिहाड़ी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी मजदूरों को लगभग 28 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावारिपल्ली गांव में होगा। इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि मजदूरी समय पर मिल सके और काम चलते रहें।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हैं। चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। केंद्र और राज्यों ने मिलकर वीबी-जी राम-जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी।

अवैध मकानों को खाली करने के नोटिस पर धमतरी में बवाल

धमतरी, 1 जुलाई। रायपुर के नकटी गांव के बाद धमतरी के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। 50 से अधिक मकानों को खाली करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद ग्रामीणों और राजस्व टीम के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई। मौके पर कुछ समय के लिए स्थिति गर्मा गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की यह कार्रवाई पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि एक निजी संस्थान को जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग दबाव बनाकर लोगों को उनके घरों से हटाने की कोशिश कर रहा है। धमतरी में भी रायपुर के नकटी गांव जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि संबंधित भूमि पर 50 से अधिक मकान अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को घर खाली करने का नोटिस और अल्टीमेटम दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और कार्रवाई का विरोध जताने लगे। इस दौरान राजस्व अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित लोगों को जल्द से जल्द अतिक्रमित भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

झगड़े से तंग आकर सौतन की हत्या

बालोद, 1 जुलाई। रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर महिला ने अपनी सौतन को आधी रात को मौत के घाट उतार दिया. दूसरे कमरे में सो रही सौतन को महिला ने पहले खाट के खुले से पीटा, फिर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना बालोद जिले के नेवारीकला गांव की है, जहां सोमवार को आरोपी महिला अमृत बाई साहू ने दूसरे कमरे में सो रही अपनी सौतन दया बाई साहू की हत्या कर खेत के तरफ भाग गई. रात में करीबन 3 बजे जब पति चिम्मन साहू की नींद खुली तो देखा कि उसके साथ सो रही अमृत बाई गायब है.

विधायक ने सीएम को लिखा पत्र-नकटी में नहीं चाहिए आवास

रायपुर,1 जुलाई। सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चातुरीनंद डिग्रीलाल नंद द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए एक पत्र ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विधायक ने पत्र में दो टूक शब्दों में कहा है कि नकटी गांव में गरीबों का घर उजाड़कर उन्हें (विधायक को) सरकारी आवास नहीं चाहिए। इस संवेदनशील कदम के बाद कांग्रेस ने अब सत्ताधारी दल भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, सरायपाली विधायक चातुरीनंद डिग्रीलाल नंद को नकटी गांव में आवास आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर उनका आवास प्रस्तावित है या बनाया जाना है, वहां पहले से कुछ गरीबों के घर बसे हुए हैं और उन्हें हटाया जा सकता है, तो उन्होंने तुरंत कड़ा रुख अपनाया।

विधायक ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना आवंटन या दावा छोड़ने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया: "मुझे गरीबों के आशियाने की कीमत पर कोई सरकारी बंगला या आवास नहीं चाहिए। नकटी गांव में जिन गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, वह सरासर गलत है। मैं ऐसे किसी भी फैसले के खिलाफ हूं जो आम जनता और गरीबों को बेघर करे।" इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं और नेताओं ने चातुरीनंद के इस कदम को 'सच्ची जनसेवा और नैतिकता' का उदाहरण बताया है।कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल दागा है।कांग्रेस का कहना है कि जहां एक तरफ भाजपा सरकार में गरीबों पर बुलडोजर चलने और उन्हें बेघर करने की खबरें आती हैं, वहीं कांग्रेस की महिला विधायक ने जनहित में अपने विशेषाधिकार को छोड़ दिया। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा, "क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक या मंत्री ऐसा नैतिक साहस दिखा पाएगा? क्या वे गरीबों के हक में अपनी सुख-सुविधाओं को लात मारने का दम रखते हैं?"

स्कूल के सफाईकर्मी ने कुएं में कूदकर दी जान

गरियाबंद,1 जुलाई। विवाद के बाद युवक ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 35 वर्षीय लोकेश कुमार यादव के रूप में हुई है. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. जानकारी के अनुसार, पूरा मामला देवभोग थाना इलाके के कुदलीमुड़ा गांव का है. मृतक लोकेश स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है. कुएं से शव को बाहर निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई की गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है.

रायपुर।मकान तोड़े जाने के विरोध में आज ग्राम नकटी की महिलाओं ने कलेक्टोरेट का घेराव किया।

पुरस्कार राशि को लेकर टेनिस खिलाड़ियों में असंतोष

सफलता में संदेह और अपार कमाई से उभरा विचार

आलेख .. जसवंत क्लॉडियस, वरिष्ठ स्वतंत्र खेल पत्रकार, टी वी कमेंटेटर, रायपुर,छ ग

समय समय की बात है खेल कभी मनोरंजन के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए के लिए खेली जाती थी परंतु धीरे-धीरे अब खेल का व्यावसायिकरण हो गया है। खेल एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। आधुनिक काल के खिलाड़ियों के लिए खेल मनोरंजन करने, स्वस्थ रहने और धन कमाने का मार्ग बन गया है। बहुत पहले टेनिस कुलीन वर्ग का खेल था . आज संसार में जगह जगह टेनिस की प्रतियोगिता साल भर कहीं न कहीं होती रहती है . टेनिस में ग्रैंडस्लेम स्पर्धाओं को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक टेनिस खिलाड़ी की चाहत होती है कि वह जीवन में कम से कम एक बार ग्रैंड स्लेम जीत ले। टेनिस में ग्रैंड स्लेम याने आस्ट्रेलियाई ओपन (1905 से मेलबॉर्न में), फ्रेंच ओपन (1891से पेरिस में),विंबलडन (1877 से लन्दन में) तथा अमेरिकी ओपन (1881से न्यूयार्क में) प्रत्येक वर्ष इसी क्रम से आयोजित की जाती है। उपरोक्त चारों चैंपियनशिप में आस्ट्रेलिया ओपन जनवरी (महीने के मध्य से अंत तक) फ्रेंच ओपन मई-जून (मई के अंत से जून की शुरुवात तक) विबलडन (जून जुलाई (जून के अंत से जुलाई के आरंभ तक)यू एस ओपन अगस्त-सितंबर (अगस्त के अंत से सितंबर के प्रारंभ तक) प्रत्येक वर्ष संपन्न होती है।

मुझे खेल पत्रकारिता के 48 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद यह कभी सुनने में नहीं आया कि पुरस्कार राशि को लेकर कभी टेनिस खिलाड़ियों तथा आयोजकों में कोई असंतोष हुई. खेलकूद जिसे अनुशासन और समय की पाबंदी का प्रतीक माना गया है, अब ताज्जुब लग रहा है कि उससे जुड़े खिलाड़ी ग्रेड स्लेम में मिलने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। टेनिस खिलाड़ियों की पहल को हम अनुशासनहीनता कहे या नहीं? फिलहाल खेल की दुनिया के पत्रकारों, खेल समावलोचकों को लिए इसका उत्तर देना होगा। आखिर करोड़ों रुपये कमाने वाले टेनिस खिलाड़ी इनाम में अधिक धनराशि चाहते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी।

आज के प्रतिष्ठापूर्ण समाज में रहने का स्तर काफी ऊंचा हो गया है घर, बंगला, आदि जरूरी सुविधा एक खिलाड़ी के पास होनी चाहिए अब घर में जिम और उसे प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षिक जरूरी है। 20वीं सदी में खेल में स्वयं को फिट रखने के लिए ऐसी आधुनिकतम सुविधा की शायद जरूरत नहीं रही होगी लेकिन आज टेनिस में बनने वाले एक विश्व चैंपियन के लिए सहयोगी स्टाफ के रूप में पर्सनल मैनेजर, ट्रैवल एजेंट को भी रखना पड़ता है . इस प्रकार खान पान, कसरत, स्वास्थ्य आदि की देखरेख के लिए कम से कम 13से 18 स्टाफ की आवश्यकता होती है। घर में लगाने वाले जिम की सामग्री करोड़ों रुपये की आती है जिसमें भी प्रत्येक 3-4 वर्ष में उन्नयन होते रहता है। इसी तरह खाद्य पदार्थ भी कीमती हो गई है। फिर तरह-तरह के कार का शौक भी कम महंगा नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए टेनिस खिलाड़ी ग्रेंड स्लेम में अधिक पुरस्कार राशि की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रेंड स्लेम में नाम से आयोजकों द्वारा मीडिया प्रसारण और होने वाले मैच में प्रवेश टिकिट की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। आस्ट्रेलिया ओपन में पहले दिन के पहले मैच के लिए कई दिनों पूर्व एडवांस बुकिंग के माध्यम से लगभग 30 हजार रुपये एक सेशन के लिए प्रत्येक दर्शक से लिया जाता है। हालांकि फ्रेंच ओपन और अमेरीकी ओपन के लिए एक टिकिट की दर करीब पचास से साठ हजार रुपये लगती है। विंबल्डन में तो और भी महंगा है। वहां स्टेडियम में प्रवेश हेतु निश्चित दौर के लिए एक से डेढ़ लाख तक की टिकिट मिलती है। उपरोक्त चारों ग्रेंडस्लेम के मुख्य स्टेडियम में 14800 से 23700 तक दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इस प्रकार अनुमानतः प्रत्येक ग्रेंड स्लेम में 80 करोड़ रुपये से लेकर 120 करोड़ रुपये टिकिट विक्रय से प्राप्त होता है। इसके अलावा मीडिया प्रसारण से प्राप्त राजस्व अलग है। अर्थात आज के युग में मीडिया मैनेजमेंट करने वाले स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ग्रेंड स्लेम का आयोजन करने वाले वस्तुतः सब खर्च के बाद कितनी राशि बचा लेते हैं। 20 वीं सदी के खिलाड़ियों के समक्ष ज्यादा चुनौती नहीं थी और वे अपने आपको किसी चैंपियनशिप के लिए तैयार करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च नहीं करते थे और उनका खेल जीवन लंबा होता था। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में कौन सा खिलाड़ी किस चैंपियन को हरा दे कहं नहीं सकते और टेनिस खिलाड़ियों में बढ़ते हुए संघर्ष ने उनके मन में भयऔर शंका को जन्म दे दिया है इसलिए ग्रेंड स्लेम खेलने वाले खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें मिलने वाली पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। आज टेनिस में हम जो देख रहे हैं अब ग्रेंड स्लेम टाइटिल किसी एक खिलाड़ी की बपौती नहीं है। इन सब परिस्थितियों में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं टेनिस खिलाड़ियों की मांग समय के अनुरूप है और इसे अनुशासनहीनता नहीं कहा जा सकता .

बारिश के मौसम में सर्पदंश से बचाव,उपचार के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कवर्धा, 1 जुलाई। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ सर्पदंश की घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति ने जिलेभर में विशेष जनजागरूकता अभियान शुरू किया है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और वनांचल में रहने वाले लोगों को सर्पदंश से बचाव के उपायों तथा समय पर उपचार के प्रति जागरूक करना है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुरे ने बताया कि बारिश के मौसम में सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में खेतों, झाड़ियों, जलभराव वाले क्षेत्रों के साथ-साथ घरों और गोठानों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में खेतों में कार्य करते समय गमबूट या ऊंचे जूते पहनना, झाड़ियों या गड्ढों में हाथ डालने से पहले डंडे से जांच करना तथा रात के समय टॉर्च का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने घर और आसपास की झाड़-झंखाड़ हटाने तथा खुले स्थान या फर्श पर सोने से बचने की भी सलाह दी।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सर्पदंश होने पर घबराने के बजाय पीड़ित को शांत रखें और प्रभावित अंग को यथासंभव स्थिर रखें। प्रभावित स्थान पर चीरा लगाना, जहर चूसने का प्रयास करना, कसकर रस्सी बांधना या झाड़-फूंक जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए पीड़ित को निकटतम शासकीय स्वास्थ्य संस्थान पहुंचाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 108 या 112 पर कॉल कर निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया जा सकता है। जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में सर्पदंश के उपचार के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा दल तथा पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) उपलब्ध है। समय पर उपचार मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मितानिनों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सर्पदंश से बचाव संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है। जागरूकता, सतर्कता और समय पर चिकित्सा ही सर्पदंश से होने वाली मौतों और गंभीर जटिलताओं को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है।

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का भारतीय टीम में हुआ चयन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम शहर में 4 से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाली एशिया-पैसिफिक-अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय (महिला एवं पुरुष) पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए पावरलिफ्टिंग इंडिया ने प्रदेश के चार प्रतिनिधियों का भारतीय टीम में चयन किया है।117 सदस्यीय भारतीय दल में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जयदीप साहू, अमान शुक्ला तथा प्रियांक मिश्रा को खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिक, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक कृष्णा साहू को भारतीय टीम का कोच बनाया गया है। कृष्णा साहू को विक्रम, गुंडाधुर एवं वीर हनुमान सिंह खेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि जयदीप साहू, अमान शुक्ला और प्रियांक मिश्रा पहली बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश की धरती पर किसी अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं कृष्णा साहू खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अंतरराष्ट्रीय निर्णायक के रूप में अपना 33वां अंतरराष्ट्रीय दायित्व निभाएंगे। कोच कृष्णा साहू ने बताया कि सेक्टर-6 स्थित पावर जिम में खिलाड़ियों को व्यवस्थित एवं कठिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय दल 4 जुलाई को मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। टीम में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुल 12 खिलाड़ी शामिल रहेंगे।

एक नजर

2 लाख के गांजा सहित तस्कर गिरफ्तार

भिलाई, 1 जुलाई (तछसं.)। भिलाई खुर्सीपार थाने पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग दो लाख रुपए का गांजा जब्त किया है पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (ख), 27 ए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है खुर्सीपार टीआई आनंद शुक्ला ने बताया कि थाना खुर्सीपार क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर रोड बिहारी मोहल्ला के सामने नहर पार खुर्सीपार में एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का विक्रय कर अवैध लाभअर्जित कर रहा है। सूचना पर थाना खुर्सीपार पुलिस तत्काल टीम गठित कर बताए गए स्थान पर घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हरिशंकर यादव उर्फ जुगनु यादव (24 साल) निवासी दुर्गा मंदिर के पास खुर्सीपार बताया। विधिवत तलाशी लेने पर उसके कब्जे से बिक्री के लिए रखा गया 4 किलो 198 ग्राम अवैध गांजा, बिक्री रकम तथा एक एक्टिवा वाहन बरामद किया है ।

गांजा ले जाते दो युवक गिरफ्तार

भिलाई, 1 जुलाई (तछसं.)। भिलाई वाहन चेकिंग के दौरान गांजा का परिवहन करते दो युवकों को नंदिनी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है आरोपियों के कब्जे से 5.189 किलोग्राम गांजा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया है नंदिनी टीआई अनिल पटेल ने बताया कि थाना नंदिनी पुलिस ने ग्राम मुरमुंदा आम रोड में अवैध वस्तुओं के परिवहन की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मोटर साइकिल में दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर संदेहियों को रोका। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सत्ती साहू उर्फ माया साहू, (27 साल) तथा त्रिलोचन साहू उर्फ जय प्रकाश, (30 साल) दोनों निवासी ग्राम सरोरा थाना उरला जिला रायपुर बताया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 5.189 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ साथ ही परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध थाना नंदिनी में धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है ।

गांजा बेचने वाला गिरफ्तार

भिलाई, 1 जुलाई (तछसं.)। भिलाई छावनी पुलिस ने बताया कि 29 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि हीरो होंडा शोरूम के पीछे खंडहर के पास एक व्यक्ति अपने पास रखे बैग में मादक पदार्थ गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। मौके पर पहुंचकर नाबालिग को पकड़कर उसके कब्जे से 2.456 ग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजा की कीमत 1 लाख 22 हजार 8 रुपए आंकी गई है छावनी थाने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है ।

शराब पीने पैसे नहीं दिए तो की खुदकुशी

भिलाई, 1 जुलाई (तछसं.)। भिलाई छावनी थाना क्षेत्र के एक युवक अपने पिता से शराब पीने पैसे की मांग की पिता ने पैसे नहीं दिया तो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। छावनी थाना प्रभारी रामनारायण धुरवे ने बताया कि घटना सोमवार की है संतोषी पारा निवासी अतुल सिंह चौहान (24 साल) घर आया और पिता को शराब पीने पैसे मांगे। पिता ने पैसे नहीं दिये तो उसने अपने पास रखा पेट्रोल खुद के शरीर में डालकर आग लगा दिया आनन-फानन में परिजन उसे सेक्टर-9 अस्पताल ले गए जहां देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मर्ग कायम कर लिया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया 27 स्वयं सहायता समूहों को 1.08 करोड़ का बैंक ऋण वितरित

दुर्ग, 1 जुलाई। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विकासखंड पाटन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की रणनीराई एवं दिग्गाभाटा शाखाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु सतत समन्वय एवं अनुश्रवण किया गया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल से जून 2026 की अवधि में कुल 27 स्वयं सहायता समूहों को 1,08,50,000 करोड़ रुपए (एक करोड़ आठ लाख पचास हजार रुपये) का बैंक ऋण वितरित किया गया।

भाजपा ने धरना-प्रदर्शन कर कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी भिलाई-3 एवं चरोदा मंडल तथा नगर निगम भिलाई-चरोदा के भाजपा पार्षदों के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस शासित नगर निगम भिलाई-चरोदा की कार्यप्रणाली के विरोध में जंगी धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार, जनविरोधी नीतियों और विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए तथा इनकी निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्य वक्ता एवं भाजपा जिला संगठन प्रभारी रामजी भारती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की शहर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य प्रभावित हैं, जबकि आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने आरोप लगाया कि नगर निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। जिला प्रवक्ता प्रेम लाल साहू ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केवल घोषणाएं हुई हैं, जबकि धरातल पर अव्यवस्था और कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, पिछड़े, श्रमिक और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ा है। विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू ने आरोप लगाया कि निगम की लापरवाही के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। सभा को पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीता साहू, नेता प्रतिपक्ष रामखेलावन वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय, तुलसी ध्रुव तथा पार्षद फिरोज फारूकी, अपर्णा दास गुप्ता, सत्यप्रकाश शर्मा, तुशांत वर्मा और संजय यादव ने भी संबोधित किया।

अभियान

बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की दो बूंदे पिलाई गई

कवर्धा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत वार्ड नंबर 27 कवर्धा केंद्र क्रमांक 2 बुथ क्रमांक 35 पर बच्चें को पोलियो ड्रॉप्स की दो बूंदे पिलाई गई ।

जिले में पीएम आवास प्लस 2.0 की चयन प्रक्रिया जारी 80 हजार से अधिक हितग्राही प्रारंभिक सूची में पात्र

दुर्ग, 1 जुलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वे सूची के माध्यम से वास्तविक परिवारों को लाभांवित करने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ जारी है। योजना के तहत ऐसे परिवारों को जोड़ा गया है, जिनके नाम सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 या आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं थे। जिले में कुल 95,783 हितग्राहियों का सर्वे किया गया था, जिसमें से 81,600 का सर्वेयरों द्वारा और 14,183 का हितग्राहियों द्वारा स्वयं (सेल्फ सर्वे) कर भौतिक सत्यापन कराया गया। भारत सरकार के आवास सॉफ्ट पोर्टल द्वारा ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद प्रारंभिक रूप से 80,835 हितग्राही पात्र और 14,948 हितग्राही अपात्र श्रेणी में दर्ज हुए हैं। इस सूची को पारदर्शी बनाने और त्रुटियों को सुधारने के लिए विगत 24 जून 2026 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जहां सूची का सार्वजनिक वाचन कर प्राथमिकता तय की गई। स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए ग्राम पंचायत डूमरडीह में 32 अपात्र प्रकरणों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया।

विधायक देवेंद्र ने की भिलाई की बसाहट बचाओ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। विधायक देवेंद्र यादव ने सोमवार को भिलाई की बसाहट बचाओ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत सेक्टर-2 से की। अभियान के पहले दिन उन्होंने पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ घर-घर पहुंचकर नागरिकों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और इस मुहिम में सहयोग एवं समर्थन देने की अपील की। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा टाउनशिप में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही सेक्टर-9 अस्पताल सहित बीएसपी क्षेत्र की बसाहट को कमजोर कर निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भिलाई की पहचान, सामाजिक संस्कृति और वर्षों से बसे परिवारों के भविष्य पर किसी भी प्रकार का संकट स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे भिलाई के अस्तित्व, सम्मान और विरासत की रक्षा का अभियान है। इसलिए सभी नागरिकों से धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि पूरा शहर साथ खड़ा होगा तो भिलाई की बसाहट को कोई भी नहीं उजाड़ पाएगा। अभियान के तहत सेक्टर-2 के वार्ड-56, सड़क-15 तथा वार्ड-55, सड़क-12 में बैठकें आयोजित की गईं। विधायक ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं और चिंताएं सुनीं तथा भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा और टाउनशिप को बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान पार्षद साधना सिंह, विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र परघनिया, रमाकांत देशलहरे, सेक्टर-4 के राजेश चौधरी, सेक्टर-3 के पार्षद सुरेश वर्मा, हरिश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

किसानों को मिली राहत, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिलेगी यूरिया खाद

दुर्ग, 1 जुलाई। राज्य सरकार के फैसले से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2026 के दौरान किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यूरिया की वर्तमान पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पूर्व में जारी कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।उप संचालक कृषि श्री संदीप भोई ने बताया कि किसानों को यह उर्वरक एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा। सहकारी समिति में यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पंजातानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त की जा सकेगी।जिले में किसान भाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर श्री अभिजित सिंह के मार्गदर्शन में सतत् भंडारण एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिले में खरीफ 2026 हेतु कुल 67880 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर जिले में 22688 मीट्रिक टन यूरिया, 4376 मीट्रिक टन डीएपी, 11725 मीट्रिक टन एनपीके, 5901 मीट्रिक टन एमओपी तथा 11067 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 55757 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण किया गया है।

आयुक्त ने विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा लेकर सभी कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बुधवार को जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सीसी रोड, सीवर सिस्टम पाइपलाइन तथा बैक लाइन की कच्ची नालियों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ओम शांति चौक से कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड के बीच निर्माणाधीन सीसी रोड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना क्षेत्र में सीवर सिस्टम पाइपलाइन और बैक लाइन की कच्ची नालियों की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। आयुक्त ने बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए नालियों की नियमित एवं समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जलभराव की स्थिति न बने और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्वेता वर्मा, उप अभियंता अशोक देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी शंकर सहानी, स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह सहित जोन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पद्मश्री सम्मानित समाजसेवियों का नागरिक अभिनंदन किया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। महाराष्ट्र मंडल, सेक्टर-4 में आठ धार्मिक एवं समाजसेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में दंतेवाड़ा क्षेत्र में वर्षों से निस्वार्थ सेवा कार्य कर रहे पद्मश्री सम्मानित दम्पती रामचंद्र ज्वंकर गोडबोले एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता गोडबोले का नागरिक सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पद्मश्री डॉ. बुधरी ताती का भी सम्मान किया गया।

जामुल में सियान सदन एवं अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जामुल,1 जुलाई। नगर पालिका जामुल के वार्ड 18 में सियान सदन का लोकार्पण एवं वार्ड 10 में परशुराम चौक हेतु चबुतरा निर्माण कार्य एवं वार्ड 20 में शिव मंदिर के पास डोम शेड निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय विधायक एवं अनुसुचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, विधायक प्रतिनिधी सतीश साहू सहित पार्षदगण खम्हन ठाकुर, दीपक गुप्ता, सीमा यादव, कविता विश्वाल, रामदुलार साहू, चुम्मन वर्मा, अहिल्या वर्मा, शांति टंडन सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य एवं जनप्रतिनिधीगण एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

नगर निगम के 8 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई विदाई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 1 जुलाई। नगर निगम भिलाई में सेवानिवृत्त हुए आठ कर्मचारियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्हें शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनके लंबे, समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाकाल के लिए सम्मानित किया गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में समयपाल एवं कार्य सहायक ग्रेड-2 बंछोर लाल, पम्प सहायक विष्णु प्रसाद साहू, संजीव तिवारी, अनिल कुमार शर्मा, प्रकाश साहू, वाहन चालक विश्राम सिंह वर्मा, चौकीदार बसंत तथा सफाई कामगार कोटेश्वर को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। इस अवसर पर आयुक्त एवं उपायुक्त ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन की कामना की। विदाई समारोह में निगम के उपायुक्त डी.के. कोसरिया, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उद्यान एवं जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता फत्ते लाल साहू, के.के. सिंह, शशिभूषण मोहंती, राज सच्चर, सागर दुबे सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

PM आवास योजना के तहत 172 आवासों के लिए आवेदन आमंत्रित

भिलाई, 1 जुलाई। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के अंतर्गत आवास आवंटन के लिए पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

निगम द्वारा शासन को भेजे गए कुल 4,372 आवासों के प्रस्ताव में से 4,200 आवास व्यवस्थापन के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष 172 आवासों के लिए सामान्य पात्र आवेदकों से आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक आवेदक 3 जुलाई तक जोन-3 कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक नजर

नगर में 10 वें योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ सप्तिमं के हॉल में

डोंगरगढ़ 1 जुलाई। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नगर में योग को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं योगगुरु स्वामी रामदेव के पुरुषार्थ और परमार्थ के संकल्प को आत्मसात करते हुए डोंगरगढ़ में 10 वें योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ 1 जुलाई को प्रातः 5.30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपरी हॉल में किया जाएगा। वर्तमान में नौ योग केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं। इनमें मां बमलेश्वरी योग केंद्र छिरपानी, बुद्धविहार योग केंद्र, सामुदायिक भवन एवं गार्डन योग केंद्र कालकापारा, खालसा योग केंद्र, बाल मंदिर योग केंद्र, गोंडवाना धर्मशाला योग केंद्र प्रातः एवं सायंकाल, स्टेडियम योग केंद्र सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। अब सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू होने वाला यह केंद्र नगर का दसवां योग केंद्र होगा। योग केंद्र के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पालिकाध्यक्ष रमन डोंगरे उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में योगाचार्य डीसी ऐडे, विश्वनाथ यादव, हेमंत साहू विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता योग समिति के अध्यक्ष संतोष टेमरे करेंगे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर योग केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य प्रकाश यादव के विशेष सहयोग से प्रारंभ हो रहे इस केंद्र में प्रतिदिन अनुभवी योग शिक्षक एमडी साहू एवं उज्ज्वल वर्मा द्वारा नियमित योगाभ्यास कराया जाएगा। आयोजकों का उद्देश्य डोंगरगढ़ को योग हब के रूप में विकसित करना और अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना है। सेवा सेतु के प्रबंधक फ्रिोज सर्वा ने नगरवासियों से नए योग केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने तथा नियमित योगाभ्यास अपनाकर स्वस्थ, सुंदर और निरोगी जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।

अल-नीनो का प्रभाव, किसानों को कृषि कार्य के लिए एडवाइजरी जारी

बलौदाबाजार,1 जुलाई। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अल-नीनो प्रभाव संबंधी पूर्वानुमान को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के लिए कृषि कार्य संबंधी आवश्यक एडवाइजरी जारी की गई है। किसानो से अपील की है कि अल-नीनो की परिस्थितियों को देखते हुए कम एवं मध्यम अवधि में पकने वाली फसलों तथा किस्मों का चयन करें, जिससे वर्षा की अनिश्चितता वर प्रभाव कम हो। वर्तमान में कम वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान की सीधी बुआई को प्राथमिकता दें। रोपा खेती में अधिक पानी एवं लागत की आवश्यकता होती है तथा पक्ल पकने में अतिरिक्त समय लगता है। धान की सीधी बुआई (सी.एस.आर.) विधि से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है। फसल की कास्त लागत लगभग 5000 रूपये प्रति एकड़ कम होती है, तथा फसल 12 से 15 दिन पहले पक जाती है। उच्चहन भूमि वाले क्षेत्रों में धाम के स्थान पर दलहनी फसलें जैसे अरहर, मूंग एवं उड़द तथा तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली, तिल, रामतिल एवं सोयाबीन की खेती अपनाएं। फसलों की बुवाई कतार पद्धति से करें। इससे खरपतवार नियंत्रण, पौधे की उचित वृद्धि एवं नमी संक्षण में सहायता मिलती है।सभी फसलों के बीजों का बुवाई पूर्व फफूंदनाशी-कार्बन्डाजिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज , वहिप्राशी थायमेथोक्सान, इमिडाक्लोप्रिड-1.5 मि.ली. प्रति किलोग्राम बीज, जैव उर्वरक धान हेतु एजोरिपरित, अन्य फसलों हेतु एजोटोबैक्टर तथा दलहनी फसली हेतु राइजोनियम का अवश्य उपयोग करें। यदि बुवाई के पश्चात् 15 जुलाई तक अंकुरण नहीं होता है, तो पुनः बुवाई करें तथा सामान्य बीज दर की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक बीज का उपयोग करें। जुलाई माह के अंत तक मूंग एवं उड़द की बुवाई पूर्ण कर लें। अगस्त माह में तिल, सूरजमुखी राठा मध्यम अवधि पाली अरहर की बुवाई की जा सकती है। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण हेतु अनुशंसित खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, जिससे मि?ट्टी में नमी का संरक्षण बना रहे। आवश्यक्तानुसार फसलों में मल्चिंग का उपयोग करें। इससे भूमि की नमी संरक्षित होती है तथा फसलें सूखे के प्रभाव से सुरक्षित रहती हैं। गांव के नालों पर सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर अस्थायी बांध बनाएं तथा वर्षा जल का संचयन करें। कम वर्षा की स्थिति में नत्रजन उर्वरकों का उपयोग सीमित मात्रा में करें। इसके स्थान पर 2 प्रतिशत पुरिया धोल का छिड़काव अधिक लाभकारी रहेगा अथवा एक एड़क में 2 बोतल पैनो यूरिया का उपयोग करें।कृषि कार्यों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए अपने निकट स्थित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं।

आपदा पीड़ित परिवारों को 8 लाख की आर्थिक सहायता मंजूर

बलौदाबाजार,1 जुलाई। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। प्राकृतिक आपदा से मृत दो व्यक्ति के निकट परिजन प्रत्येक के लिए 4 लाख के मान से 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिजन सोमू प्रधान पिता शिवशंकर प्रधान, निवासी ग्राम कुम्हारी , तहसील टूंडरा एवं संतोष साहू पिता रोहित साहू, निवासी ग्राम मोहतरा , तहसील बलौदाबाजार की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़ 1 जुलाई। विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठीटोला के आश्रित ग्राम नवागांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित रूप से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने सचिव व रोजगार सहायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आवास योजना में नाम शामिल कराने और पहल तैयार करने के नाम पर प्रत्येक पात्र हितग्राही से एक-एक हजार रुपये लिए। इसके बावजूद ग्रामसभा में जारी अंतिम सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफकड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि, ग्राम नवागांव के लगभग 90 पात्र परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

दिलाने के नाम पर एक-एक हजार रुपये की राशि ली गई। शिकायत में रोजगार सहायक दिलीप चौधरी, इंजीनियर प्रदीप खरे तथा कोटवार सरकाश लाउने पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों ने घर-घर जाकर हितग्राहियों का सत्यापन किया, उनके मकानों की तस्वीरें लीं और भरोसा दिलाया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल हो चुका है।

ग्रामसभा में प्रस्तुत सूची में नाम गायब

ग्रामीणों का आरोप है कि 24 जून को आयोजित ग्रामसभा में जब प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन किया गया, तब जिन 90 परिवारों से कथित रूप से राशि ली गई थी, उनमें से किसी का भी नाम सूची में नहीं था। सूची से नाम गायब होने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। उनका कहना है कि उनसे सहयोग राशि लेने के बावजूद योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला।

कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने जिलाधीश से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कथित रूप से वसूली गई राशि की जांच कर उसे वापस दिलाने तथा सभी 90 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और पंचायत सचिव को उनके पद से हटाने की मांग भी की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे जिला मुख्यालय पहुंचकर भूख हड़ताल करेंगे।

बायपास निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस का चक्काजाम, दो घंटे थमा रहा यातायात

विधायक हर्षिता स्वामी बघेल के नेतृत्व में प्रदर्शन, परिक्रमा पथ का निर्माण निरस्त करने की उठाई मांग

डोंगरगढ़ 1 जुलाई। शहर में लंबे समय से लंबित बायपास निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने विधायक हर्षिता स्वामी बघेल के नेतृत्व में डोंगरगढ़-खैरागढ़ मुख्य मार्ग स्थित हाई स्कूल चौक पर चक्काजाम किया। करीब दो घंटे तक चले आंदोलन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को आत्मानंद स्कूल के बगल से राधिका नगर और नया बस स्टैंड मार्ग की ओर डायवर्ट कर दिया, जबकि भारी वाहनों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया। पूरे आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम एम. भार्गव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर के लिए बायपास निर्माण को पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए परिक्रमा पथ निर्माण को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है।

आम नागरिकों की तुलना में कुछ चुनिंदा लोगों को अधिक लाभ मिलेगा- ज्ञापन में कहा गया है कि डोंगरगढ़ में प्रस्तावित परिक्रमा पथ का मूल उद्देश्य धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ना बताया गया था, जबकि वर्तमान में सभी प्रमुख धार्मिक स्थल पहले से ही सड़कों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में करोड़ों रुपये खर्च

कर परिक्रमा पथ का निर्माण जनहित में नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस परियोजना से आम नागरिकों की तुलना में कुछ चुनिंदा लोगों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह योजना सरकारी धन की बर्बादी है और शहर की वास्तविक आवश्यकता बायपास सड़क है।

भारी वाहनों की आवाजाही होने से यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा- कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्षों से बायपास निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। शहर के बीच से प्रतिदिन भारी वाहनों की आवाजाही होने से यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर लगभग 10 लोगों की मौत और कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन बायपास के बजाय परिक्रमा पथ निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस पहले भी कई बार प्रशासन से सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, मुख्य मार्ग के प्रमुख चौक-चौराहों पर स्थायी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती तथा बायपास निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग कर चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन इन मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा- कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यदि एक सप्ताह के भीतर प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इसी चेतावनी के तहत मंगलवार को चक्काजाम किया गया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक बायपास निर्माण को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरना-प्रदर्शन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान, जिला कांग्रेस महामंत्री विजयराज सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश भंडारी की गैरमौजूदगी भी पूरे प्रदर्शन के दौरान चर्चा का विषय बनी रही।

पंचायतों में निर्माणाधीन बाजार शेड में अनियमितता की शिकायत करेंगे ग्रामीण

- पंचायत के नाम का उपयोग कर नियम विरुद्ध ठेकेदार से लिया जा रहा है कार्य
- यात्री प्रतीक्षालय की तर्ज पर बाजार सेट निर्माण में लाखों रुपए का बंदर बाट कर रहे हैं जिम्मेदार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़ 1 जुलाई। विकास खंड के विभिन्न ग्रामों में निर्मित यात्री प्रतीक्षालय निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार की तर्ज पर ग्राम पंचायत मोहरा सहित विभिन्न ग्राम पंचायतो में निर्मित अथवा निर्माणाधीन बाजार शेड के निर्माण में संबंधित विभाग व भिलाई निवासी ठेकेदार द्वारा भारी पैमाने में अनीयमितता किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। विधायक निधि से स्वीकृत 10 लाख की लागत में से संबंधितों द्वारा आपस में मिलकर लाखों रुपए का बंदरबाट करने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। ग्राम शिवपुरी एवं मोहरा के जिम्मेदार ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने की तैयारी की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक निधि से स्वीकृत राशि पंचायत को तो जारी की गई किंतु निर्माण कार्य भिलाई निवासी ठेकेदार द्वारा संपन्न कराया गया। जो पंचायती राज नियम के विरुद्ध है। बेलगांव में भी भिलाई के ठेकेदार द्वारा कार्य कराने की बात सामने आ रही है। मोहरा में निर्मित बाजार शेड निर्माण में एस्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया है। संपूर्ण सामग्री निम्न स्तर की लगाई गई है। शेड का निर्माण रोड से नीचे अधिक गहराई में किया गया है। बैठने के लिए शेड के नीचे भाग को मात्र समतल करके छोड़ दिया गया है।अधिक गहराई में होने के कारण बरसात के समय पानी की निकासी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

पंचायत के निर्माण कार्यों में कमीशन के अलावा ठेका पद्धति - राज्य शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं दिए जाने से विकासखंड के विभिन्न पंचायतो में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने में पंचायत के प्रतिनिधियों को अनेक मुसीबतो का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे विपरीत समय में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियो द्वारा जो राशि पंचायत को जारी की जा रही है,उसमें भारी पैमाने में कमीशन खोरी किए जाने की बात सामने आ रही है। ग्राम पंचायत के सरपंच हर शर्तो पर अपने यहां निर्माण कार्य स्वीकृत करना चाहते हैं। ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा का लाभ मिल सके। यही कारण है कि जिस भी निर्माण कार्य के लिए जनपद सदस्य,जिला पंचायत सदस्य, विधायक अथवा सांसद की ओर से ग्राम पंचायत को राशि स्वीकृत की जा रही है,उसमें प्रमुख शर्त 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के अलावा स्वयं के पसंदीदा ठेकेदार से कार्य संपन्न करना होता है। जो पंचायती राज व्यवस्था का माखौल उड़ाने जैसा है।

डायल-112 की तत्परता: सड़क हादसे में घायल युवक को समय पर पहुंचाया अस्पताल

बलौदाबाजर 1 जुलाई। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। सुहेला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रानीजरौंद और टेकारी के बीच दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचकर त्वरित और सराहनीय कार्रवाई की। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 भाटापारा ग्रामीण (वाहन बाज 01) को इवेंट मिलते ही टीम सुबह ठीक 11:30 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर डायल 112 के आरक्षक 823 महेंद्र साहू और चालक मुकेश रजक ने स्थिति को संभाला। इसी दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए थाना सुहेला (वाहन बाज 01) के स्टाफ आरक्षक छत्रपाल वर्मा भी तुरंत मौके पर पहुंचे।

तिल्दा-नेवरा में तीन शालाओं के संयुक्त शाला प्रवेश उत्सव में नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत

- सौरभ जैन, पार्षद रानी सौरभ जैन, एवं पार्षद किरण बाला छबड़िया समेत जनप्रतिनिधि रहे मौजूद, प्रतिभावान छात्राओं व समिति सदस्यों का हुआ सम्मान

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

तिल्दा-नेवरा, 1 जुलाई। शिक्षा सत्र के शुभारंभ के साथ ही तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में शाला प्रवेश उत्सव की धूम रही। सोमवार को रुरहा राम वर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवरा क्रमांक-1, शासकीय प्राथमिक शाला तिल्दा बस्तल एवं शहीद हेमू कलानी तिल्दा कैंप तीनों शालाओं में संयुक्त रूप से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया। कार्यक्रम में कक्षा पहली और कक्षा छठवीं के नव प्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और पुस्तकें भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तिल्दा भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष सौरभ

जैन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद रानी सौरभ जैन, वार्ड 17 की पार्षद किरण बाला छाबड़िया, जनसेवक सुधा केशरवानी, शाला विकास समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष राजेंद्र केशरवानी मंच पर उपस्थित थे। बीएनबी संकुल के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार चंदानी, हायर सेकेंडरी स्कूल केसदा के प्राचार्य विनोद वर्मा, प्राथमिक शाला तिल्दा बस्तल के सेवानिवृत्त शिक्षक भागीरथी पांसे और अति वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक राम अवतार पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही।

शाला विकास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों ने बच्चों को पुस्तकें और मिठाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया। अतिथियों के प्रेरणादायी उद्बोधन और छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने शाला प्रवेश उत्सव में चार चांद लगा दिए। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर शाला विकास समिति की अध्यक्ष तीजन नौरंगे, उपाध्यक्ष रानी गोस्वामी तथा कार्यकारिणी सदस्य कुसुम निषाद, कलेश्वरी ध्रुव, माधुरी ध्रुव, पुष्पा मानिकपुरी, सुनीता धीरे, शतरूपा, प्रभा यादव, शंकर लाल यादव, कमल साहू एवं शिक्षाविद अनिरुद्ध वर्मा को बीते वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए मोमेंटो और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का भी सम्मान हुआ। कक्षा आठवीं की छात्रा रिया गिरी को राष्ट्रीय सह संसाधन छात्रवृत्ति पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और कुमारी माया निषाद को कक्षा आठवीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वार्ड 21 की पार्षद रानी सौरभ जैन ने सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं को पेन वितरित किए। कार्यक्रम का सफल संचालन बीएनबी संकुल के संकुल समन्वयक लेखराज सोनी ने किया। शाला प्रवेश उत्सव को सफल बनाने में तीनों शालाओं के प्रधानपाठक, शिक्षक-शिक्षिकाओं और शाला परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया

रायपुर 1 जुलाई। बोरिया खुर्द प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें अतिथि के रूप में पार्षद श्रीमती सुषमा तिलक साहू व प्रयास इंस्टिट्यूट की डायरेक्टर कविता कुम्भज उपस्थित हुए उन्होंने बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर तथा पुस्तक कॉपी पेंसिल देकर उनका भव्य स्वागत किया, और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे स्कूल में हमेशा रेगुलर आए क्योंकि हमारे भविष्य की नींव बचपन में ही रखी जाती है, बच्चों के द्वारा रंगारंग नृत्य संगीत का भी आयोजन किया गया प्राचार्य श्रीमती रेखा शर्मा ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बड़े हर्ष के साथ बताया कि हमारे विद्यालय के बच्चे विद्यालय के अलावा बाहर होने वाली प्रतियोगिता यो में भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे विद्यालय की कक्षा 9वीं की अन्यनिया अज़रिया को 28 तारीख को मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव सहाय जी द्वारा निबंध प्रतियोगिता में सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है,तथा pp2 की छात्रा इशिता ठाकुर ने कराटे में सिल्वर मेडल प्राप्त कर स्टेट खेलने का अवसर पाया है, हमारे स्कूल के विद्यार्थी हर प्रकार की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अभिभावक और विद्यार्थी सभी मिलजुलकर आगे की रणनीति बनाते हैं और उसे पर उज्जवल भविष्य की उम्मीदों को साकार करने का प्रयास करते हैं।

मुक्त छत्तीसगढ़ एवं वैचारिक घुसपैठ विषय पर बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन

रायपुर 1 जुलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच रायपुर चैप्टर द्वारा माओवाद मुक्त छत्तीसगढ़ एवं वैचारिक घुसपैठ विषय पर बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया था।जिसके मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार जी, मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच एवं वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही भारत अलगावबाद का दंश झेल रहा है।पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू हुआ यह सिलसिला कश्मीर से पंजाब होते हुए मध्य भारत तक फैला।कहीं अलगाववाद,तो कहीं आतंकवाद,तो पंजाब में खालिस्तान की मांग हो।भारत के आदिवासी क्षेत्रों में माओवादियों ने अपनी जड़ों को मजबूत किया।माओवाद की आड़ में धर्मांतरण तीव्र गति से फैला। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और स्थानीय लोगों की संकल्प से छत्तीसगढ़ में माओवादियों को पिछे हटना पड़ा है। लेकिन अब सरकार और समाज की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है कि माओवादी पुनः पैर न पसारे इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय लोगों को सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत किया जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। घर की कामकाजी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए ताकि एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो सके। छोटे - छोटे समूहों में लोगों को संगठित कर उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति से रूबरू कराया जाए।जिससे धर्मांतरण को रोका जा सकता है। आदिवासी संस्कृति और उनके विरासत को पुरा सम्मान और पहचान मिले,जिससे उन्हें गर्व की अनुभूति होगी।इस कार्य में सरकार के अलावा छोटे बड़े सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षाविद्, पत्रकार,पायलट,व्यवसायी, वकील, समाजसेवी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस नेक कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तभी हम माओवादियों और धर्मांतरण जैसे वैचारिक लड़ाई से जीत पाएंगे।कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच रायपुर चैप्टर के अध्यक्ष तौकीर रजा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि 70 के दशक में माओवाद अंकुरित हुआ और धीरे धीरे पुरे देश में फैलते गया।चुंकि छत्तीसगढ़ माओवाद से मुक्त हो गया है तो हम सभी को मिलकर एक नये समाज का निर्माण में सहयोग करना चाहिए।इस अवसर पर डॉ वर्णिका शर्मा,राष्ट्रीय महामंत्री,मनु नाहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ भूपेंद्र कुमार साहू महामंत्री रायपुर चैप्टर ने किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन में रितेंद्र नायक महामंत्री एवं रेखा शर्मा सचिव रायपुर चैप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अतिक्रमण है तो कानूनन हटाया ही जाएगा

गलत काम करने वाले भी जानते हैं कि वह आज गलत काम कर रहे हैं तो कल इस गलत काम के कारण उनको या उनके परिवार को नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। फिर भी गलत काम करने वाले गलत काम करते हैं तो उनको होने वाली तकलीफ,आंसू देख सुनकर जाहिर तौर पर बुरा तो लगता है कि इनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लेकिन यह भी ख्याल आता है कि इनको तो मालूम था वह जो काम कर रहे हैं उसके कारण एक दिन उनको तकलीफ तो होगी फिर यह काम इन्होंने किया है तो कहा जा सकता है कि यह आंसू व यह तकलीफ तो इनकी नियति थी और इसके लिए वह भी जिम्मेदार हैं।नकटी गांव के वे लोग ऐसे हैं जिनके अवैध कब्जे में बने मकान सोमवार को तोड़े गए हैं।साय सरकार के सुशासन पर सवालिया निशान लगाने वाले कह रहे हैं कि क्या यही सुशासन है।ऐसे लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सुशासन तब ही होता है जब कोई भी कहीं भी शासकीय जमीन पर कब्जा कर ले और सरकार जमीन को उनके नाम कर दे। ऐसा सुशासन तो छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस व विपक्ष शासित किसी राज्य में नहीं होगा। जहां भी अवैध कब्जा किया गया है, वहां तो कभी न कभी कानूनन हटाया ही जाएगा। नकटी में यही किया गया है। जिनके अवैध कब्जे में बनाए गए मकान तोड़े गए हैं, उनका कहना है कि जल्दी में यह काम किया गया है इससे उनको सामान हटाने का मौका नहीं मिला,उनको परेशानी हुई, उनके बच्चों को परेशानी हुई।यह सच नहीं है नकटी गांव के लोगों को क्या राजधानी के तमाम लोगों को मालूम है कि अवैध कब्जे हटाने का नोटिस तो कुछ दिन पहले ही सभी घरों में लगा दिया गया था कि आप लोग अपना घर खाली कर दें क्योंकि तय समय के बाद मकान तोड़े जाएंगे। इसके बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में कहा था कि पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना इनको न हटाया जाए तो इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई उसके बाद अवैध कब्जे में बने ७७ मकान तोड़े गए हैं।ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन ने यूं ही लोगों के मकान तोड़ दिए हैं और उनका मकसद गरीब व मजदूर लोगों को परेशान करना था।राजस्व विभाग के मुताबिक तो यह कार्रवाई न्यायालय के अप्रैल २०२५ के अनुसार की गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने बहुत समय दिया है।अवैध कब्जाधारियों को अवैध कब्जा करने के बाद भी उम्मीद थी कि शायद उनके विरोध प्रदर्शन,कांग्रेस के विरोध के चलते अवैध कब्जा छोड़ दिया जाए। उनके मकान न तोड़े जाएं। यह उम्मीद बेकार की उम्मीद थी क्योंकि मकान अवैध कब्जे में बने थे इसलिए तोड़े गए। कांग्रेस सरकार के समय भी तोड़े जाते तो इसी कारण तोड़े जाते कि मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं, इसलिए तोड़े गए हैं। सरकार भाजपा की रहे या कांग्रेस की रहे,सरकारी जमीन पर कब्जा कोई भी करे उसे कानून हटाया ही जाता है भले ही वहां मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने का कानून तो वही रहता है सरकार किसी की भी रहे लेकिन राजनीति करनेवाला बदल जाते हैं।कांग्रेस सरकार में रहती है तो भाजपा नेता उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि अरे अरे आप लोगों के साथ सरकार ने बड़ा अन्याय कर दिया है।आज भाजपा सरकार है तो अतिक्रमणकारियों के साथ कांग्रेस नेता आकर खड़े हो गए हैं।जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की कडी निंदा कर रहे हैं,कुछ कह रहे हैं कि कितनी मेहनत से मकान बनाया था,असंवेदनशील सरकार ने तोड़ दिया।बिना मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास किया बिना ऐसी कार्रवाई तो गरीबों के साथ अन्याय है।कोई कह रहा है कि भाजपा सरकार गरीबों के दर्द व आंसुओं को समझने में विफल है। इस तरह की कार्रवाई से भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। कोई कांग्रेस नेता कह रहा है कि यदि सरकार गरीबों के साथ न्याय नहीं करती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। ऐसे समय मे एक पक्ष जब सरकार को अन्यायी बताने का प्रयास करता है तो सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वह राज्य के लोगों को बताए कि वह सुशासन वाली सरकार है,सुशासन ही उसका लक्ष्य है और वह जो करती है कि राज्य में सुशासन व जनता व राज्यहित में करती है।कलेक्टर साहब का बताना जरूरी हो जाता है कि जो कुछ किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। इसलिए गौरव सिंह ने बयान दिया है कि नकटी गांव की भूमि शासकीय परियोजना के लिए आरक्षित थी,यहा कब्जा करने वाले परिवारों को नियमानुसार आवास उपलब्ध कराया गया है। कार्रवाई के दौरान कई भावुक दृश्य लोगों ने देखा,भावुक लोगों को यह न लगे कि वाकई सरकार ने लोगों को दुख पहुंचाने का काम किया है,विधायक अनुज शर्मा ने बताया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा,सरकार विस्थापितों की पूरी चिंता करेगी।विस्थापितों के लिए जहां उनकी व्यवस्था की गई है, वहां प्रशासन ने भोजन सहित सभी व्यवस्था की है। कोई भी सरकार रहे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तो होते रहते हैं।ऐसा नहीं है कि भाजपा के समय होते हैं और कांग्रेस के समय नहीं होते हैं। इसी तरह अवैध कब्जे सरकार किसी की रहे वह हटाए जाते हैं और हटाने का एक ही तरीका होता है। कोई उसे अन्याय कह सकता है तो कोई उसे नियमानुसार की गई कार्रवाई कह सकता है। अवैध कब्जे होते क्यों हैं इसकी कई वजहें हो सकती हैं कि कुछ लोग आदतन अवैध कब्जे करने वाले होते हैं, अवैध कब्जा करते हैं और किसी को बेच भी देते हैं। कुछ लोग इस उम्मीद में कब्जा कर लेते हैं कि उसका कब्जा बाद हो सकता है कि नियमित कर दिया जाए। जैसे अवैध नल,अवैध कालोनी को नियमित किया जाता है।कई लोग इसलिए कब्जा कर लेते हैं कि अभी तो कर लेते हैं बाद में जो होगा देखा जाएगा।सराकर व जिला प्रशासन की लापरवाही भी एक कारण होती है।सरकारी जमीन पर कहीं बोर्ड नहीं लगा होता कि यह सरकारी जमीन पर इस पर कब्जा करना मना है,कब्जा करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सरकार को अवैध कब्जे का पता तब चलता है जब कोई परियोजना बनाती है।यह तो मजाक जैसा लगता है कि अवैध कब्जे और सरकारी जमीन पर सरकारी योजना के तहत सरकार के पैसे से इंदिरा आवास व पीएम आवास तक बन जाता है। बाद में उसे तोड़ भी दिया जाता है। दुनिया में कुछ शाश्वत नियम होते हैं वह बदलते नहीं है इसी तरह सरकारी,नजूल की जमीन है तो कब्जा तो होगा ही,यह नियम भी शाश्वत है कोई भी सरकार आए नहीं बदलता है और यह भी शाश्वत नियम है कि अवैध कब्जा है तो उसे कानूनन हटाया जाएगा।

विश्लेषण

भारतीयता की मिसाल पेश करती सद्भावपूर्ण कारगुज़ारियां

निर्मल रानी

दुनिया में भारत की पहचान अनेकता में एकता रखने वाले देश के रूप में बनी हुई है। विविधता ही हमारे देश की एक ऐसी सबसे बड़ी विशेषता है जो पूरे विश्व को भारत की ओर आकर्षित करती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक तरह की भाषाएं,अलग अलग रंग, अलग खानपान, विभिन्न प्रकार की पोशाकें,अनेक क़िस्म के धर्म,जातियां,रीति रिवाज,मान्यताएं तथा विश्वास आदि हमारे देश को एक रंग बिरंगे ख़ुशबूदार गुलदस्ते के रूप में दुनिया के सामने पेश करते हैं। परन्तु पिछले एक दशक में एक ऐसी साम्प्रदायिकतावादी विचारधारा ने सत्ता पर नियंत्रण हासिल कर लिया है जिसे शायद हमारे देश की यह विविधता व सर्वधर्म समभाव रास नहीं आता। यह विचारधारा पूरे देश को एक ही रंग में रंगना चाहती है। और अपने इस मक़सद को पूरा करने के लिये यह शक्तियां पूरे देश में सांप्रदायिकता व जातिवाद का ज़हर घोलने के प्रयास हो रहे हैं। दुःख की बात तो यह है कि इन दुष्प्रयासों में लगे लोग इंसानियत को भी भूल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य तो जैसे नफ़रती एजेंडे पर तेज़ी से अमल करने की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, आसाम, राजस्थान, मध्यप्रदेश,बंगाल जैसे राज्यों में कौन मुख्यमंत्री कितनी मस्जिदें गिराता है कितनी दरगाहों व मदरसों पर बुलडोज़र चलता है,कितने मुसलमानों के घर ज़मींदोज़ करता है, इसे लेकर इनमें गोया होड़ लगी हुई है। सैकड़ों मस्जिदों व मदरसों को धराशायी करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ही अभी पिछले ही दिनों संभल के नख़ासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम-कसेरुआ में स्थित ऐतिहासिक 'मुस्तफ़ा क़ादरी मस्जिद' को प्रशासन द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीक़े से बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। जबकि बताया जा रहा है कि यह मस्जिद उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गज़ट में बाक़ायदा व़'जायदाद के तौर पर दर्ज है। सवाल यह उठता है कि जो इबादतगाह राज्य सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हो, उसे रातों-रात एक सोची-समझी साज़िश के तहत 'अवैध' कैसे घोषित किया जा सकता है? इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर मस्जिद को ध्वस्त करने की एक गहरी राजनीतिक साज़िश का हिस्सा है। साफ़ है कि भाजपा सरकार मुसलमानों को निशाना बनाते हुये दमनकारी, पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक तरीक़े से अपनी 'बुलडोजर नीति' लागू कर रही है। सत्ता संरक्षित व पोषित इस नफ़रत में कुछ लोग तो इतने अंधे हो गए हैं कि लंगर भंडारा लगाते समय किसी का धर्म पूछकर उस के हाथों से प्रशाद की थाली तक वापस छीने ले रहे हैं ? धर्म जाति देखकर सार्वजनिक प्याऊ से पानी पीने तक के लिये मना कर रहे हैं ? किसी दाढ़ी टोपी वाले को लंगर की थाली देकर उसके खाने से पहले 'जयश्रीराम ' बोलने का दबाव डाला जा रहा है ? परन्तु हक़ीक़त में यह सब कुछ हो तो ज़रूर रहा है परन्तु इसके लिये सत्ता व संबंधित संगठनों को योजनाबद्ध तरीक़े से काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ रही है। इसके लिये सत्ता का दुरूपयोग भी हो रहा है और लाखों निठल्ले

बेरोज़गार व अपराधी क़िस्म के लोग सत्ता का संरक्षण पाकर बेलगाम होकर धर्म व जाति विशेष के लोगों के साथ अमानवीय तरीक़ों से पेश आ रहे हैं। परन्तु जिस देश की रगों में राम रहीम कबीर रसखान जायसी नानक फ़रीद बुल्लेशाह चिश्ती औलिया जैसे महापुरुषों संतों व फ़क़ीरों के संस्कार सीख व शिक्षाएं प्रवाहित हो रही हों उस देश पर यह संगठित नफ़रती गिरोह लंबे समय तक अपनी एकरंगी नफ़रती विचारधारा हरगिज़ नहीं थोप सकते। उदाहरणार्थ पिछले दिनों भारत सहित पूरे विश्व में करबला के शहीदों के नाम पर मुहर्रम संबंधी आयोजन किये गये। जगह जगह ताज़िये रखे गये। इस मौक़े पर पूरे देश में सैकड़ों जगह ऐसे दृश्य देखे गये जबकि हिन्दुओं ने ताज़ियादारी की और मुहर्रम मनाया। कुछ जगहें तो ऐसी भी थीं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहते परन्तु दशकों से केवल हिन्दू समाज के लोग ही ताज़िया व अलम उठाते व मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। सैकड़ों जगहों पर हिन्दू व मुसलमान बिना किसी भेदभाव के लंगर बांटते व ग़रीबों की मदद करते दिखाई दिये। बिहार में तो मुहर्रम को केवल धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि लोक एवं साझा सामाजिक संस्कृति के रूप में मनाया जाता है। अनेक हिन्दू बाहुल्य इलाक़ों में ताज़िया-जुलूस के साथ मजलिस, फ़ातिहा पढ़ने और कर्बला की घटना को याद करने की परंपरा है। बिहार के संदर्भ में तो यह भी उल्लेखनीय है कि मुहर्रम की परंपरा को कई जगह "वादा, वफ़ा और विरासत" के रूप में याद किया जाता है। यानी यह केवल शोक का आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सद्भाव, परस्पर सम्मान और साझा इतिहास का प्रतीक बन चुका है। बिहार में ही मुहर्रम का एक ख़ास ऐतिहासिक पक्ष यह भी है कि कई गांवों में हिंदू समुदाय पीढ़ियों से ताज़िया, मातम और जुलूस की परंपरा निभाता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर कटिहार के महमदिया हरिपुर गांव में पिछले सौ साल से अधिक समय से हिंदू लोग मुहर्रम मनाते आ रहे हैं, जिसे स्थानीय लोग पूर्वजों के वादे और गंगा-जमुनी तहज़ीब की विरासत से जोड़ते हैं। इसी बीच राजस्थान में कई जगहों से साम्प्रदायिक एकता व सद्भाव की ऐसी मिसालें देखने को मिलीं जिसने यह साबित कर दिया कि सत्ता की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में हिन्दू मुस्लिम एकता व भाईचारे को दुनिया की कोई भी ताक़त मिटा नहीं सकती। ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार के निर्देश पर राज्य के बाड़मेर व जैसलमेर जैसे सीमावर्ती ज़िलों में अनेक मस्जिदों को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। ज़ाहिर है इससे मुस्लिम समाज में भय व शोक व्याप्त हो गया। परन्तु इसके विरोध में भारी संख्या में स्थानीय हिन्दू समाज के पुरुष महिलाएं बुज़ुर्ग व युवा सभी ने इकट्ठे होकर सर्व धर्म शांति मार्च निकले व सभाएं आयोजित कीं। राजस्थान के हिन्दू समाज ने न केवल इन धर्मस्थलों के ध्वस्तीकरण का विरोध किया बल्कि मुसलमानों के साथ अपनी एकता व एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। कई जगह राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन स्थानीय ज़िला कलेक्टर को सौंपे गए जिसमें सरकार की इस धर्मस्थल ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया गया। लोगों ने इसे धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मुद्दा मानते हुए शांति, भाईचारे को क़ायम रखने और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। निश्चित रूप से नफ़रत फैलाने के अफ़सोसनाक राजकीय प्रयासों के बीच प्रेम,शांति व सद्भाव की ऐसी कारगुज़ारियां भारतीयता की सच्ची मिसाल पेश करती हैं।

सू- दोकू क्र.086

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र[ख] सकते है।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.085 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

शब्द सामर्थ्य -086

[illegible]

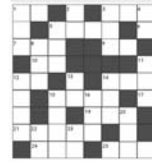

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 085 का हल

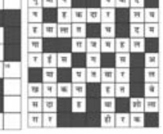

राशिफल

मेष आज का दिन आपके लिए संतोष और सहयोग से भरा रहने वाला है। परिवार और अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा। किसी दूसरे का वाहन इस्तेमाल करने से बचें। कार्यों में जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य से फैसले लेना अधिक लाभकारी रहेगा।

वृषभ आज स्वादिष्ट भोजन, परिवार के साथ हंसी-मजाक और बच्चों की चंचलता आपके दिन को खुशियों से भर सकती है। घरेलू वातावरण सुखद बना रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करना आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने निवेश से भी अच्छा संकेत मिल सकता है।

मिथुन आज का दिन धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रह सकता है। किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। दिन की सबसे खास बात किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा।

कर्क आज का दिन शांत और संतुलित ऊर्जा लेकर आया है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके मन को गर्व और प्रसन्नता से भर सकती है। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। मन में चल रही किसी चिंता का समाधान भी धीरे-धीरे निकलता नजर आएगा।

सिंह आज संतान की प्रगति आपके लिए गर्व का कारण बनेगी। स्वास्थ्य से जुड़े छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि समय पर ध्यान देना भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। किसी खास व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है।

कन्या आज आपके सामने नए अवसरों के कई रास्ते खुल सकते हैं। करियर और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। हालांकि बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बात को सकारात्मक रूप से नहीं लेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आने के योग हैं।

तुला आज आपके भीतर आगे बढ़ने और कुछ बड़ा हासिल करने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नए निर्णय लेने का साहस दिखाएंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत होगी। कोई महत्वपूर्ण योजना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है।

वृश्चिक आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की आवश्यकता है। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। जीवनसाथी के लिए कोई उपहार या विशेष खरीदारी रिश्तों में नई मिठास घोल सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा।

धनु आज सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दे रही है। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील या कार्य अचानक आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास के बल पर आप कई चुनौतियों को आसानी से पार करेंगे। यात्रा से जुड़े नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

मकर आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के संकेत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। घर के बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को हर गतिविधि पर नजर बनाए रखनी होगी। धन लाभ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं।

कुंभ आज का दिन नई जानकारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई व्यक्ति आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने साझा करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा।

मीन आज मेहनत और समर्पण आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन वरिष्ठों को प्रभावित कर सकती है। यात्रा या किसी मुलाकात के दौरान मिली जानकारी भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज समझदारी से लिया गया निर्णय फायदा देगा।

आस्था की चौखट पर असुरक्षा

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत की सांस्कृतिक पहचान केवल उसके इतिहास, भाषाओं और परंपराओं से नहीं बनती, बल्कि उन आस्था-स्थलों से भी निर्मित होती है जिन्होंने सदियों से समाज को नैतिकता, सहअस्तित्व और सामुदायिक एकता का संदेश दिया है। मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं; वे विश्वास, संस्कृति, लोकजीवन और सामाजिक सहभागिता के जीवंत केंद्र हैं। यहां लोग केवल ईश्वर के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने सुख-दुख साझा करने, मन की शांति पाने और जीवन के संघर्षों में आशा का संबल प्राप्त करने आते हैं। यही कारण है कि जब किसी मंदिर में चोरी होती है, तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता। यह करोड़ों लोगों की आस्था, सामाजिक विश्वास और सांस्कृतिक चेतना पर सीधा आघात होता है। बीते कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से मंदिरों में दानपेटियां तोड़ने, नकदी चुराने, बहुमूल्य आभूषण गायब करने, प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करने और धार्मिक सामग्री की चोरी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कई मामलों में अपराधियों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया, जबकि कई घटनाओं में अंदरूनी मिलीभगत की आशंका भी सामने आई। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि समाज के नैतिक मूल्यों और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी रह गई है। जिस स्थान को लोग सबसे सुरक्षित और पवित्र मानते हैं, यदि वही अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बनने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। मंदिरों में चोरी को सामान्य संपत्ति-अपराध की श्रेणी में रखकर उसकी गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। किसी दुकान, मकान या कार्यालय में चोरी आर्थिक क्षति पहुंचाती है, लेकिन मंदिर में चोरी विश्वास की जड़ों को भी कमजोर करती है। श्रद्धालु अपनी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, सेवा और समाजहित की भावना से दान करते हैं। वे यह विश्वास रखते हैं कि उनका अर्पण धर्मार्थ कार्यों, सामाजिक सेवा और मंदिर व्यवस्था में उपयोग होगा। जब वही धन चोरी हो जाता है, तो केवल दानपेटी खाली नहीं होती, बल्कि श्रद्धालु के मन में भी संदेह और पीड़ा जन्म लेती है। यही कारण है कि मंदिरों में चोरी की घटनाएं समाज में सामान्य अपराधों की तुलना में कहीं अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण नकद दान की परंपरा है। आज भी देश के अधिकांश मंदिरों में बड़ी मात्रा में नकद चढ़ावा आता है। अनेक छोटे और मध्यम मंदिरों में दान की गणना, सुरक्षित भंडारण और बैंक में जमा करने की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं होती। कई बार दानपेटियां लंबे समय तक नहीं खोली जातीं, जिससे उनमें बड़ी मात्रा में नकदी जमा हो जाती है। यह स्थिति अपराधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो और बड़ी मात्रा में नकद धन उपलब्ध हो, वहां अपराध की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता है। महानगरों के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक अलार्म सिस्टम, रात्रि सुरक्षा, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं या तो उपलब्ध नहीं हैं या केवल औपचारिक रूप से स्थापित हैं। कई कैमरे खराब पड़े रहते हैं, रिकॉर्डिंग का बैकअप सुरक्षित नहीं होता और नियमित निगरानी भी नहीं की जाती। अपराधी इन कमियों का अध्ययन कर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं।

प्रबंधन संबंधी कमजोरियां भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। अनेक मंदिरों का संचालन पारंपरिक ढंग से होता है, जहां वित्तीय जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता के स्पष्ट मानक नहीं बने हैं। दान की गणना, लेखा-जोखा, व्यय और भंडारण की प्रक्रिया कई बार व्यवस्थित नहीं होती। जहां जवाबदेही कमजोर होती है, वहां गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मामलों में चोरी बाहरी अपराधियों द्वारा नहीं, बल्कि अंदरूनी मिलीभगत से भी की जाती है। यह स्थिति अधिक चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इससे संस्था के भीतर का विश्वास भी टूटता है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी इस समस्या से जुड़ी हुई हैं। बेरोजगारी, नशे की लत, कर्ज का बोझ, त्वरित धन कमाने की मानसिकता और नैतिक मूल्यों का ह्रास कुछ लोगों को अपराध की ओर धकेलता है। हालांकि इन कारणों के आधार पर किसी भी अपराध का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। मंदिरों में चोरी केवल आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं होती; अनेक मामलों में यह संगठित अपराध, मूर्ति तस्करी और पेशेवर गिरोहों की सुनियोजित गतिविधि होती है। विशेष रूप से प्राचीन मूर्तियों और दुर्लभ धार्मिक कलाकृतियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध मांग भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। मंदिर में चोरी का सबसे गहरा प्रभाव श्रद्धालुओं की भावनाओं पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार की खुशहाली, बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक दान करता है, तो वह केवल धन नहीं देता, बल्कि अपना विश्वास भी समर्पित करता है। यदि वही विश्वास असुरक्षित महसूस करने लगे तो समाज में धार्मिक संस्थाओं के प्रति संदेह बढ़ने लगता है। कई लोग दान देने से हिचकने लगते हैं, मंदिर समितियों पर प्रश्न उठने लगते हैं और स्थानीय स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण बन जाता है। इस प्रकार एक चोरी केवल धन का नुकसान नहीं करती, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक एकता को भी प्रभावित करती है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को केवल धार्मिक विषय मानना भी पर्याप्त नहीं है। यह सार्वजनिक नीति, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। जिस प्रकार बैंक, संग्रहालय, विद्यालय और सार्वजनिक संस्थानों के लिए सुरक्षा के मानक निर्धारित होते हैं, उसी प्रकार मंदिरों के लिए भी न्यूनतम सुरक्षा मानक तय किए जाने चाहिए। प्रत्येक मंदिर की आय, आकार और संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकती है। बड़े मंदिरों में अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था, नियंत्रित प्रवेश, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और डिजिटल प्रबंधन आवश्यक है, जबकि छोटे मंदिरों में स्थानीय पुलिस, ग्राम समितियों और नागरिकों के सहयोग से प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित किया जा सकता है।

आज के डिजिटल युग में तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे, क्लाउड आधारित रिकॉर्डिंग, गति-संवेदी अलार्म, बायोमेट्रिक प्रवेश प्रणाली, स्मार्ट लॉक और आपातकालीन सूचना प्रणाली मंदिरों की सुरक्षा को मजबूत बना सकती हैं। दानपेटियों को निर्धारित समय पर ही खोला जाए और यह प्रक्रिया कम-से-कम दो या तीन जिम्मेदार व्यक्तियों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। नकद गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग, हस्ताक्षरित रजिस्टर और बैंक में तत्काल जमा की व्यवस्था से अनियमितताओं की संभावना काफी कम हो सकती है।

डिजिटल दान प्रणाली भी समय की आवश्यकता बन चुकी है। यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी व्यवस्थाएं नकदी पर निर्भरता कम कर सकती हैं। इससे चोरी का जोखिम घटेगा और दान की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल रसीद उपलब्ध कराई जा सकती है तथा मंदिरों की आय और व्यय का वार्षिक विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। पारदर्शिता बढ़ने से श्रद्धालुओं का विश्वास भी मजबूत होगा और प्रबंधन की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सुरक्षा व्यवस्था केवल उपकरणों से मजबूत नहीं होती; उसके लिए उत्तरदायी प्रबंधन भी आवश्यक है। मंदिर समितियों को नियमित आंतरिक और बाहरी ऑडिट कराना चाहिए। आय-व्यय का स्वतंत्र परीक्षण, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बहुमूल्य आभूषणों का सुरक्षित भंडारण और समय-समय पर भौतिक सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। जहां जवाबदेही स्पष्ट होगी, वहां भ्रष्टाचार और चोरी की संभावनाएं स्वतः कम होंगी। समाज की भूमिका भी इस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी धार्मिक स्थल की सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। स्थानीय समुदाय, श्रद्धालु, स्वयंसेवी संगठन और मंदिर समितियां यदि सामूहिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करें तो अपराधियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। पड़ोस की सतर्कता, संदिग्ध गतिविधियों की समय पर सूचना और सामुदायिक निगरानी कई अपराधों को घटित होने से पहले ही रोक सकती है। मंदिर केवल पुजारियों या ट्रस्ट की संपत्ति नहीं हैं; वे पूरे समाज की सांस्कृतिक धरोहर हैं। नैतिक शिक्षा का भी इस संदर्भ में विशेष महत्व है। यदि बचपन से ही बच्चों और युवाओं में ईमानदारी, सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान और धार्मिक स्थलों की गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाए तो अपराध की मानसिकता को जड़ से कमजोर किया जा सकता है। विद्यालयों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को यह संदेश देना होगा कि मंदिरों की सुरक्षा केवल ताले और कैमरों से नहीं, बल्कि चरित्र और संस्कारों से भी होती है। कानून भय पैदा कर सकता है, लेकिन नैतिकता अपराध की इच्छा को समाप्त करती है।

कानून व्यवस्था को भी ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी बनाना होगा। यदि मंदिरों में चोरी संगठित अपराध, मूर्ति तस्करी या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से की गई हो तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। जांच में देरी, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और कमजोर अभियोजन अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रभावी अभियोजन और समयबद्ध न्याय से ही यह संदेश जाएगा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि भविष्य के अपराधों को रोकना भी होना चाहिए।

बालविवाह की सूचना पर प्रशासन ने दिखाई तत्परता

टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बीजापुर 1 जुलाई। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा जिले में संचालित बाल विवाह रोकथाम एवं जन-जागरूकता अभियान का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जागरूक नागरिकों द्वारा समय रहते चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचना देने के कारण एक संभावित बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोका गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार, जिले के भोपालपटनम विकासखंड के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन टीम तत्काल मौके पर पहुँची। टीम ने किशोरी के माता-पिता सहित उपस्थित ग्रामीणों एवं परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा इसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश एवं विधिक परामर्श के बाद परिजनों ने बाल विवाह नहीं करने तथा बालिका की शिक्षा निरंतर जारी रखने की सहमति व्यक्त की। संबंधित परिवार से भविष्य में बाल विवाह न कराने का लिखित आश्वासन भी लिया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक एवं कानूनी अपराध है।जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग ने नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। जिले में लगातार चलाए जा रहे प्रचार-प्रसार, ग्राम स्तरीय बैठकों, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों तथा सामुदायिक संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है।

समाचार संक्षेप

सेवानिवृत्त शिक्षकों को कलेक्टर ने शॉल श्रीफल एवं पेंशन प्रमाण पत्र प्रदाय कर दी विदाई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बीजापुर, 1 जुलाई। कलेक्टर विश्वदीप ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक लक्ष्मिन्धर मांझी एवं सोमेश्वर राव को शॉल, श्रीफल एवं पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने दोनों प्रधान अध्यापकों के स्वास्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके लंबे एवं समर्पित योगदान की सराहना की।

लक्ष्मिन्धर मांझी वर्ष 1987 में सहायक शिक्षक के रूप में भोपालपटनम विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पिछूर में नियुक्त हुए थे। लगभग 39 वर्षों की सेवा के उपरांत वे 30 जून 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला नुकनपाल के प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। इसी प्रकार सोमेश्वर राव का सहायक शिक्षक के रूप में प्रथम नियुक्ति दिनांक 02 जुलाई 1993 को हुई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में लगभग 33 वर्षों तक सेवाएं प्रदान कीं तथा प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान कलेक्टर ने दोनों सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों के सेवाकाल की जानकारी ली।

पुलिस विभाग के वेतन भुगतान में डेढ़ करोड़ की हेरा-फेरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर, 1 जुलाई। बस्तर जिला पुलिस विभाग में वेतन भुगतान में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की हेरा-फेरी के मामले में वेतन शाखा के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर के दौरान अपने और कुछ अन्य विभागीय कर्मचारियों के खातों में निर्धारित वेतन से कई गुना अधिक राशि स्थानांतरित कर रहे थे।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह गड़बड़ी पिछले आठ से नौ महीनों से जारी थी। मामला विशेष ऑडिट सॉफ्टवेयर के जरिए सामने आया, जिसमें वेतन मद में भुगतान और वास्तविक राशि के बीच बड़ा अंतर पाया गया। इसके बाद खातों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ। जांच में वेतन शाखा के तीन से अधिक कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि अतिरिक्त राशि किन-किन खातों में भेजी गई और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की क्या भूमिका रही।

एक नजर

घर से सोना निकलवाने का झांसा देकर 5 लाख की ठगी करने वाले 6 आरोपित गिरफ्तार

कांकेर, 1 जुलाई। जिले के बांदे थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में रिपोर्ट दर्ज होने के महज चार दिन के भीतर अंधविश्वास का फायदा उठाकर घर से सोना निकलवाने और बीमारी दूर करने का झांसा देकर पांच लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों 1. भोला गवते पिता पिसाराम गवते उम्र 40 वर्ष जाति सरोली, 2. मुकेश सोनेष्वर पिता पिसाराम सोनेष्वर उम्र 31 वर्ष जाति सरोली, 3. शिवागिरी पिता सुरेश गिरी उम्र 28 वर्ष जाति बारड़, 4. लिलाधर शिवाजी वाघमारे उर्फ निलेश पिता शिवाजी वाघमारे, उम्र 35 वर्ष, जाति सरोदी, 5. परमेश्वर एकनाथ उर्फ देवा पिता पिसाराम एकनाथ उम्र 37 वर्ष, 6. दिनेश सोनेष्वर पिता ईश्वर सोनेष्वर उम्र 30 वर्ष को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर आज मंगलवार को कांकेर लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की 4 लाख 96 हजार रुपये की रकम भी बरामद कर ली है।बांदे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला बांदे थाना क्षेत्र के पीवी-104 दीपनगर के पीड़ित बलराम सरकार के घर एक व्यक्ति साधु के वेश में पांच पैर वाले नंदी बैल के साथ पहुंचा और घर में गड़ा सोना होने और परिवार की बीमारी दूर करने का झांसा दिया। उसने महंगी आयुर्वेदिक भस्म खरीदने और विशेष पूजा कराने की बात कहकर पीड़ित से पहले 52 हजार रुपये और बाद में 4 लाख 44 हजार रुपये की दवा खरीदवा दी। पूजा-पाठ के दौरान कथित कलश निकालकर उसे सोने से भरा बताया गया और डराया गया कि, बिना अनुमति खोलने पर परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। बाद में जब पीड़ित ने कलश खोला तो उसमें सोने की जगह पीतल की मूर्तियां निकलीं।

कांग्रेस विधायक ने जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

बीजापुर, 1 जुलाई। जिले के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने नक्सली मामलों में वर्षों से जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा है कि बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। जिसके चलते बस्तर संभाग के जेलों में नक्सलियों के नाम पर कई गरीब, निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को जेल भेजा गया है, ये लोग कई वर्षों से जेल में बंद है। आदिवासी ग्रामीण कम पढ़े-लिखे होने और आर्थिक पारेशानी के कारण न्यायालय तक नही जा पाते हैं, जिससे जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी रिहा नही हो पाते है। कांग्रेस विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान में बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। हथियार बंद आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी पुनर्वास नीति के तहत सरकार ने माफी दिया है, तो जो निर्दोष आदिवासी नक्सली मामलों में वर्षों से जेलों में बंद है उन्हें भी माफी देते हुए जेल से रिहा किया जाये।

शासकीय आयोजनों में अब सिर्फ देवभोग के उत्पादों का होगा स्वाद

जगदलपुर, 1 जुलाई।राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा अब जिले में आयोजित होने वाले सभी शासकीय आयोजनों, बैठकों, सम्मेलनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा उत्पादित देवभोग ब्रांड के दूध और दुग्ध उत्पादों का ही उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दूरगामी निर्णय का मुख्य उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े राज्य के स्थानीय पशुपालकों और किसानों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने जारी परिपत्र में निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) के नियम 8.4 के अंतर्गत यदि राज्य शासन की कोई विभागीय इकाई सामग्री का निर्माण करती है, तो उससे सीधे सामग्री क्रय करने का प्रावधान है। इसके तहत शासकीय कार्यालयों को देवभोग के प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को खरीदने के लिए अलग से कोई निविदा जारी टेंडर बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे सीधे दुग्ध महासंघ से इन उत्पादों को प्राप्त कर सकेंगे।

8 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार

जगदलपुर, 1 जुलाई। जिले के थाना बोधघाट पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर रायपुर की ओर परिवहन करने के लिए जगदलपुर बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ की टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल बस स्टैंड में पहुंचकर मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम सुका धुरवा पिता भीमा धुरवा उम्र 45 वर्ष निवासी केंदुगुडा नदीपारा थाना व्यापारी जिला कोरापुट उड़ीसा का रहने वाले बताया जिसका तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 8 किलो बरामद कर आरोपी को आज सोमवार को गिरफ्तार किया है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करें: कलेक्टर

महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने पर दिया जोर भी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बीजापुर 1 जुलाई। साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर विश्वदीप ने सभी विभागों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने पर जोर देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का समय-सीमा में समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल शीघ्र ही पुनः प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना से वंचित रह गए हितग्राहियों तथा नए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उनके आवश्यक दस्तावेजों का शत-प्रतिशत संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर बल दिया।बैठक में विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री राहत योजना पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इसके माध्यम से अधिकारियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति को समय पर इसका लाभ प्राप्त मिल सके।बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्पेशल लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को

जगदलपुर, 1 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर जगदलपुर में 18 जुलाई को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत प्रकरणों का निराकरण हेतु स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह विशेष लोक अदालत गोविंद नारायण जांगडे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर के मार्गदर्शन एवं कु. अंकिता कश्यप व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर द्वारा आयोजित की जाएगी।इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करते हुए पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर न्याय प्रदान करना है। स्पेशल लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट्स चेक बाउंस से संबंधित मामलों में दोनो पक्षों-परिवादी एवं आरोपी को आपसी सहमति से विवाद का समाधान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

आवास 2.0 पात्रता सूची में नाम कटने से जनता में नाराजगी,जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

छुरा, 1 जुलाई। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बैनर तले मंगलवार को फिगेश्वर विकासखंड के सैकड़ों ग्रामीणों ने गरियाबंद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना की पात्रता सूची में छूटे हुए हितग्राहियों के नाम शामिल करने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि फिगेश्वर विकासखंड के 10 से 15 गांवों के अनेक गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों ने शासन द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। इसके बावजूद भी उनका नाम आवास 2.0 की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पात्र होने के बावजूद उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा जाना गंभीर लापरवाही है।उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल सूची में शामिल करने और उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की।जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई कर गरीब परिवारों को राहत प्रदान की जाए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष भोजराम नेताम, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना उपाध्यक्ष महावीरा ध्रुव, राजिम खड़ अध्यक्ष लीकेश साहू सहित बड़ी संख्या में अक्रोशित जनता उपस्थित रहे।

वन विभाग का ट्रक पलटने के महीने भर बाद भी न मुआवजा मिला न दोषी लोगों पर कार्रवाई हुई

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 1 जुलाई। बस्तर जिले के कोलेंग वन परिक्षेत्र में वन विभाग का ट्रक पलटने के मामले में पीड़ित पक्षों ने विभाग पर मुआवजा न देने और दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। घटना में एक हमाल की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल सहित पांच अन्य हमाल घायल हुए थे। दुर्घटना के एक महीने बाद भी पीड़ित परिवार आर्थिक सहायता और न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। मृतक की पत्नी बसंती बघेल ने आज मंगलवार को बताया कि उन्हें विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखने का केवल मौखिक आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई आधिकारिक मुआवजा नहीं मिला है।दुर्घटना के समय केबिन में सवार हमाली के अनुसार नियमित ड्राइवर नीलकंठ धुरव की अनुपस्थिति में गाड़ी हेल्पर बंसी गोयल चला रहा था। हमालों का कहना है कि बंसी ने उन्हें बैक फेल होने की बात कही थी, जिसके बाद मोड़ पर वाहन पलट गया। हेल्पर बंसी गोयल ने भी चर्चा में स्वीकार किया है कि बैक फेल होने के समय ट्रक वही चला रहा था।

यह मामला 26 मई 2026 का है, जब दरभा वन परिक्षेत्र कोलेंग से लकड़ी के गोले (कास्ट) लोड करके लौटते समय वन विभाग का ट्रक घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक पर सवार हमाल उमेश बघेल (निवासी तराईगुड़ा) की लकड़ी के नीचे दबने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मिठू राम कश्यप का हाथ टूट गया और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा सुकरु बघेल, परशु, जयमन, मोहन और खोडिया को भी चोटें आईं, जिन्होंने अपना इलाज स्वयं करवाया। मृतक के भाई सुकरू का आरोप है कि विभाग ने तात्कालिक सहायता के रूप में केवल 50 हजार रुपये दिए हैं, जबकि अंतिम संस्कार और अन्य कार्यों में इससे अधिक राशि खर्च हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मिठू राम कश्यप के परिजनों का कहना है कि उन्हें इलाज या दवाई के लिए विभाग की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और वे एक महीने से काम करने में असमर्थ हैं।मामले की जांच कर रहे एसडीओ (वन) योगेश राजे ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और विभाग मृतक की पत्नी को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में चालक की संलिप्तता या दोष सिद्ध होते ही उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी

बकावंड के पांच गांवों में मनाया गया जल अर्पण दिवस, लिया जल संरक्षण का संकल्प

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 1 जुलाई। बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड अंतर्गत ग्राम जैतगिरी, सरगीपाल, गिरोला, डुकाबेड़ा और बदलावंड में विगत दिवस जल अर्पण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर जल संरक्षण एवं पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डबरी एवं तालाब निर्माण करने तथा जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इनमें पेयजल स्रोतों के आस-पास सोख्ता गड्ढों का निर्माण, घरों में उपयोग किए गए पानी का साग-सब्जी की बाड़ी में पुनः उपयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे कदम शामिल रहे।इस अवसर पर महिला जल वाहिनी की सदस्य महिलाओं ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ मिलकर जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसके माध्यम से पानी बचाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। जल जीवन मिशन की आईईसी ज्योत्सना सुना ने ग्रामीणों को जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, शुद्ध पेयजल के महत्व को समझने, जल संसाधनों की सुरक्षा करने, नियमित जल कर भुगतान करने, सोख्ता गड्ढों और किचन गार्डन की उपयोगिता तथा स्थानीय स्तर पर पौधरोपण कर उनकी देखरेख करने जैसे विषयों पर समझाइश दी। साथ ही ग्रामीणों को इन कार्यों में निरंतर सकारात्मक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।इस कार्यक्रम में उक्त सभी पांचों ग्रामों के सरपंच, पंचायत पदाधिकारी, महिला जल वाहिनी की सदस्य महिलाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सामुदायिक सहभागिता के साथ आयोजित यह पहल जल संरक्षण के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता और जिम्मेदारी परिलक्षित हुई।

अनछुए पर्यटन स्थल मिचनार घाटी में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या

जगदलपुर, 1 जुलाई। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर लोहंडीगुड़ा ब्लाक की मिचनार घाटी पर्यटन क्षेत्र में तेजी से अपनी साख बना रही यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। पर्यटक यहां ऐसे खिंचे चले आते हैं मानों यहां की वादियां, फिजाएं अपने दीदार के लिए बुला रही हों। मानसून का मौसम आते ही मिचनार घाटी का दृश्य चारों ओर फैली हरियाली, बादलों को चूमती पहाड़ियां और चट्टानों से गिरते झरने यहां आने वाले हर सैलानी का मन मोह लेते हैं। मानसून की बूंदों ने मानों पूरी वादियों का श्रृंगार कर दिया है। बस्तर जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय भी अब इस क्षेत्र को विकसित करने के प्रयासों में जुटे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बस्तर की पारंपरिक सुंदरता और आधुनिक पर्यटन के बीच का यह संतुलन इसे अन्य पर्यटन स्थलों से अलग बनाता है। यहां के शांत वातावरण में फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए अद्भुत लैंडस्केप मौजूद है, तो वहीं ट्रेकिंग का शौक रखने वालों के लिए छोटी पहाड़ियां रोमांच का अवसर देती हैं। पिछले कुछ समय में मिचनार घाटी में पर्यटकों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब न केवल स्थानीय लोग, बल्कि बस्तर से बाहर के सैलानी भी इस अनछूए पर्यटन स्थल की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।

कलेक्टर ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए दिए निर्देश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 1 जुलाई। राज्य शासन द्वारा राज्य में विशेष आवश्यकता वाले इन बच्चों की सही पहचान, उनके प्रामाणिक सत्यापन और अद्यतन डेटा संकलन के लिए इस वृहद सर्वेक्षण अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना है। उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आकाश छिकारा ने जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यापक सर्वेक्षण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत इसे जिला स्तरीय समय सीमा बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रत्येक स्तर पर इसकी निरंतर समीक्षा की जा सके और कार्य में कोई शिथिलता न आए। इस पूरे अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के आपसी तालमेल और मैदानी स्तर पर समन्वित पहल सुनिश्चित की जाएगी।इस दिशा में कलेक्टर ने उक्त तीनों विभागों को उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपते हुए सकारात्मक प्रयास करने को कहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मेडिकल आकलन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसके साथ ही विभाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी और उसकी गंभीरता का भौतिक सत्यापन करेगा और पात्र बच्चों का यूनिक आईडी पोर्टल पर पंजीकरण कराने में सहयोग प्रदान करेगा। बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मार्गदर्शन देने के साथ-साथ विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा और बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों की सही पहचान के लिए साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं भी ली जाएंगी। इस अभियान में समाज कल्याण विभाग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण तय की गई है, जिसके तहत विभाग अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और पुनर्वास कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी सर्वे टीम के साथ साझा करेगा। सर्वे के दौरान मैदानी स्तर पर चिन्हित होने वाले दिव्यांग बच्चों को उनकी पात्रता के अनुसार इन योजनाओं से तुरंत लिंक किया जाएगा ताकि उन्हें शासन की मदद मिल सके। साथ ही विभाग अपने पास पूर्व से उपलब्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांगता आईडी से जुड़े डेटा को भी साझा करेगा ताकि सर्वेक्षण का कार्य अधिक सुगम और त्रुटिहीन बनाया जा सके। शुरुआती स्तर पर बच्चों की पहचान को मजबूत बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को सक्रिय किया गया है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी। विभाग की टीमें कुपोषित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी साझा करने के साथ-साथ घर-घर जाकर समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक हस्तक्षेप के जरिए बच्चों में दिव्यांगता के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर उन्हें समय पर आवश्यक सहायता और उपचार प्रदान करना है।

एक नजर

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से मिली राहत, राजेश कुमार पटेल को मिला नया राशन कार्ड

रायगढ़, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। शासन की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम लोगों के लिए प्रभावी मंच बनकर उभर रही है, जहां दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम नवागांव निवासी राजेश कुमार पटेल की शिकायत का त्वरित निराकरण करते हुए उन्हें नया राशन कार्ड जारी कर उसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है।जनपद पंचायत खरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम नवागांव निवासी राजेश कुमार पटेल ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार प्रयास किया था, लेकिन आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो सका था। इसके चलते उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 12 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हुआ और मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पात्रता का परीक्षण किया गया, जिसमें वे राशन कार्ड के लिए पात्र पाए गए। इसके बाद नियमानुसार उनका नया राशन कार्ड जारी कर उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई। शिकायत के त्वरित निराकरण से हितग्राही को बड़ी राहत मिली है।राजेश कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यवस्था ने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मुख्यमंत्री की यह पहल प्रदेश में सुशासन और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण कर शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है।

एकलव्य विद्यालय छर्राटांगर में रिक्त सविदा पदों पर भर्ती के लिए 3 जुलाई को वॉक-इन-इंटरव्यू

रायगढ़, 1 जुलाई। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्राटांगर, विकासखंड घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संविदा आधार पर रिक्त पदों की भर्ती हेतु 3 जुलाई 2026 को प्रात: 8 बजे से विद्यालय परिसर में वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संविदा आधार पर होगी और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक की जाएगी। रिक्त पदों में पीजीटी राजनीति विज्ञान, पीजीटी इतिहास, पीजीटी अर्थशास्त्र और काउंसलर के एक-एक पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों का अंग्रेजी माध्यम (सीबीएसई) में दक्ष होना अनिवार्य है तथा एनईएसटीएस एवं ईएमआरएस के निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इससे पहले भी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया था, लेकिन उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रह गए थे। शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए पुन: भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट emrschharratangar.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना लिखित चयन प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को

रायगढ़, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए लिखित चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई, रविवार को किया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिले में इस परीक्षा के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय, गढ़अमरिया, रायगढ़ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विद्यालय के प्राचार्य को परीक्षा का केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है।

पॉन्ड मैन रामवीर तंवर ने की कलेक्टर अविनाश मिश्रा से मुलाकात

धमतरी, 1 जुलाई। देश में जल संरक्षण, तालाबों के सौंदर्यीकरण, मृत जल निकायों के पुनर्जीवन और शहरी वन विकसित करने के लिए प्वॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध श्री रामवीर तंवर ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच जिले में जल संरक्षण एवं तालाबों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।कलेक्टर श्री मिश्रा ने श्री तंवर से उनके द्वारा देशभर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा धमतरी जिले के मकई तालाब और कांटा तालाब के सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास पर भी चर्चा की।इसके पश्चात श्री रामवीर तंवर ने भखारा स्थित आमा तालाब का विस्तृत निरीक्षण एवं सर्वे किया। आमा तालाब को रामसर साइट घोषित कराने की दिशा में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ड्रोन कैमरे के माध्यम से जल क्षेत्र, जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आवास तथा तालाब के पारिस्थितिकीय महत्व का विस्तृत आकलन किया

कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित

राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:कलेक्टर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 1 जुलाई। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की प्राथमिकता वाले प्रत्येक राजस्व कार्य का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में आयोजित मैदानी राजस्व अमले की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अमलो को सम्मानित किया जाएगा, वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का मूल्यांकन उसकी कार्य-प्रगति, गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

कलेक्टर ने जिले की सभी तहसीलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक तहसील के एक-एक पटवारी को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही जिन राजस्व अमलों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है, उनकी सूची तैयार कर आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने नक्शा बटांकन की ग्रामवार प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी राजस्व अमले को लक्ष्य निर्धारित कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर प्रगति हासिल करने वाले पटवारियों से उनके कार्य अनुभव और नवाचारों की जानकारी भी ली, ताकि अन्य क्षेत्रों में भी उसी कार्यप्रणाली को अपनाकर प्रगति में तेजी लाई जा सके।कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत शेष लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल ऋण पुस्तिका, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा, फार्मर रजिस्ट्री, मल्टीपल ओनर वाले खातों में बकेट क्लेम सहित विभिन्न ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की तहसीलवार समीक्षा की तथा सभी कार्यों को गंभीरता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित मसाहती वन से राजस्व ग्रामों की प्रगति, वनाधिकार पट्टाधारियों के फौती नामांतरण तथा अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन के आवेदनों का त्वरित पंजीयन कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामीणों को राजस्व विभाग की विभिन्न सुविधाओं और प्रक्रियाओं के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए, जिससे लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके।कलेक्टर ने मिसल से खसरा मिलान के कार्य में तेलुगांव एवं मुकड़ेगा तहसीलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित राजस्व अमले को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि छोटे-छोटे राजस्व विवादों का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सामुदायिक मध्यस्थता समिति के माध्यम से किया जाए, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिले और राजस्व न्यायालयों पर अनावश्यक भार कम हो। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में लंबित प्रकरणों में तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के उपरांत राजस्व अमले के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में आरबीसी-6-4 पोर्टल एवं भू-अर्जन एप के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आरबीसी-6-4 पोर्टल से लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी, वहीं भू-अर्जन एप के माध्यम से राजस्व अभिलेखों का सुव्यवस्थित, त्रुटिरहित एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री गोकुल आर.के., अपर कलेक्टर श्री रवि राही, सभी अनुविभागों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार,

शिव शक्ति स्टील व श्रीसाई गणेश ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ श्रम न्यायालय में परिवाद दाखिल

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 1 जुलाई। जिले में औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिक हितों और पर्यावरणीय मानकों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं और नियमों के अनुपालन का जायजा लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसीलदार रायगढ़, उप संचालक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सहायक संचालक उद्योग विभाग तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने (इमुल टेक) और (रिजेनेसिस इंडस्ट्रीज) समेत अन्य औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान कारखानों में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों, कार्य प्रणाली तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का बारीकी से परीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई आवश्यक सुधारात्मक सुझाव दिए और संबंधित प्रबंधन को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों की सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

दो कंपनियों के खिलाफ श्रम न्यायालय में परिवाद

जिला प्रशासन ने बताया कि पूर्व में भी कई औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसी क्रम में शिव शक्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड और श्री साईं गणेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद संबंधित प्रबंधन के खिलाफ माननीय श्रम न्यायालय, रायगढ़ में परिवाद दाखिल किया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा, श्रमिक कल्याण तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे।

लोकओएस ऐप से मजबूत होगा ग्रामीण आजीविका मिशन एक माह का जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 1 जुलाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला स्तरीय लोकओएस ऐप प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कलेक्टर के निर्देश एवं सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों के लेखा-जोखा को डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाना था।

30 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष प्रशिक्षण अभियान में जिले के सातों विकासखंडों के स्व-सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों की इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपर दीदियों को आठ अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को लोकओएस ऐप के माध्यम से डिजिटल लेखा संधारण, वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव, लेखा प्रविष्टि एवं वित्तीय प्रबंधन की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।समापन समारोह में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे ने कहा कि स्व सहायता समूहों और ग्राम संगठनों का सशक्त लेखा प्रबंधन ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सफलता की आधारशिला है। उन्होंने सभी ई-बुक कीपर दीदियों से अपील की कि वे लोकओएस ऐप का प्रभावी उपयोग करते हुए समूहों के लेखा-जोखा का नियमित, समयबद्ध और त्रुटिरहित संधारण सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हुए अन्य समूहों के लिए प्रेरणा बनें। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह और ग्राम संगठन की इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपर दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से आए प्रशिक्षक राजेश्वर रेड्डी और मो. वाहिद को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सामाजिक समावेशन प्रकोष्ठ के जिला परियोजना प्रबंधक अविक बासु की निगरानी में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को डिजिटल लेखा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया, जिससे स्व सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। समापन अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त ई-बुक कीपर दीदियां उपस्थित रहीं।

रेत के अवैध परिवहन के मामले में विभाग ने किए 12 ट्रैक्टर जब्त

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 1 जुलाई। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में रेत से लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। लंबे समय से जंगल के रास्ते अवैध रूप से रेत की निकासी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बैहारमुडा के पास स्थित कुरकुट नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। रेत माफियाओं ने तस्करी के लिए घने जंगल के बीच से एक गुप्त मार्ग तैयार कर लिया था, ताकि मुख्य सड़कों और जांच चौकियों से बचते हुए आसानी से रेत का परिवहन किया जा सके। लंबे समय से इस रास्ते का उपयोग कर अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पी. एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी घरघोड़ा श्री आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वनपरीक्षेत्र अधिकारी श्री विक्रांत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। वन अमले ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी कर दबिश दी और मौके पर बिना वैध अनुमति एवं बिना परिवहन पास के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए 12 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया।कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को देखकर कई तस्करों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन विभाग ने रेत से लदे सभी ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त किए गए वाहनों को घरघोड़ा वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया है, जहां उनकी जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन, रेत तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों की चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

44.60 लाख की सिंदूर वाटिका निर्माण पर उठे सवाल, पहली बारिश में ही टूटने लगी सुरक्षा फेंसिंग एवं साइड का पिचिंग

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कुरूद,1 जुलाई। महानदी के किनारे ग्राम पंचायत मेघा में मेघा पुल के पास वन विभाग द्वारा 44 लाख 60 हजार रुपये की लागत से बना रहे सिंदूर वाटिका (गार्डन) का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस कार्य में फेंसिंग, आपने गार्डन के बाहर नदी किनारे पिचिंग कार्य , नागरिकों के टहलने के लिए पाथवे, गार्डन के अंदर बाथरूम, बोर व्यवस्था ,बैठने के लिए छोटा सा कमरा मुख्य द्वार, पेवर ब्लॉक और वृक्षारोपण जैसे कई काम शामिल हैं।

लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जिस स्थान पर गार्डन बनाया जा रहा है वह महानदी का तटीय क्षेत्र है। यहां गार्डन के किनारों पर अथाह खुदाई की गई है। ऐसे में बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी तट का कटाव होने की आशंका जताई जा रही है।जिला पंचायत सदस्य नीलम चंद्राकर ने निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद आरोप लगाया कि गार्डन की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे फेंसिंग पोल तार का गोड़ा अभी से कई जगहों पर गिरने लगे हैं। वहीं नदी किनारे कराई जा रही गार्डन के बाहरी पिचिंग और सुरक्षा बैटिंग भी भरभराकर टूट रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है । भविष्य में पूरा गार्डन खतरे में पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि शासन की लाखों रुपये की राशि से बनने वाले इस महत्वाकांक्षी उद्यान में मजबूत और टिकाऊ निर्माण होना चाहिए, ताकि लोगों को वर्षों तक इसका लाभ मिल सके।(1)इधर वन विभाग मोहंदी के रेंजर पंचराम साहू ने संवाददाता इस सम्बन्ध बताया कि सिंदूर वाटिका का निर्माण स्वीकृत मापदंडों के अनुसार कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है। यदि कहीं कोई कमी या नुकसान दिखाई देता है तो उसकी जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाएगा।(2)जानसिंग यादव पूर्व जनपद सदस्य उपाध्यक्ष का कहना है कि महानदी किनारे बन रही सिंदूर वाटिका क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है, लेकिन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ताकि बारिश के दिनों में किसी प्रकार का नुकसान न हो।(3)नीलम चंद्राकर जिला पंचायत सदस्य 44.60 लाख रुपये की लागत से बन रहे गार्डन में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। फेंसिंग के गोडे और नदी किनारे की पिचिंग अभी से टूट रही है । जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।(4) रेंजर पंचराम साहू मोहंदी सिंदूर वाटिका का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जा रहा है। जहां भी कमी मिलेगी उसे तत्काल सुधारने की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में 68.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़, 1 जुलाई। रायगढ़ जिले में 30 जून तक 68.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 10.4 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 150.7 मिली मीटर, पुसौर में 82.8, खरसिया में 57.1, घरघोड़ा में 31.8, तमनार में 105.6, तेलुगांव में 47, मुकडेगा में 49.8, धरमजयगढ़ में 26.8, छाल में 44.1 एवं कापू में 87.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

समयसीमा की बैठक में स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए लगेंगे विशेष शिविर:कलेक्टर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 1 जुलाई। जिले में विकास कार्यों तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, जनसेवा, रोजगार, पेयजल, आधारभूत अधोसंरचना तथा विभिन्न विभागों की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणाममूलक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करें।

कलेक्टर ने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विद्यालयवार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने सुचर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत 31 हितग्राहीमूलक योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण के लिए जिले के सभी ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी एवं अन्य मैदानी अमले की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी समन्वय के साथ शिविर आयोजित किए जाएं, जिससे कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। कलेक्टर ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को जिले में और अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग को अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा किसानों को प्राकृतिक खेती के आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभों की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती उत्पादन लागत कम करने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। कलेक्टर ने डीएमएफ मद से स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए बोर खनन जैसे कार्य वास्तविक आवश्यकता वाले स्थलों पर करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2026 से वीबीजीआरजी (विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएं।

कलेक्टर ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित 315 आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से राशन कार्ड, बी-1, राजस्व सेवाएं, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आधार कार्ड, पेयजल, वनाधिकार पट्टा सहित विभिन्न नागरिक सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सरल एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने जिले के विद्याधियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि वे उन क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें जहां शासन की योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हुआ है और उन नवाचारों को जिले में भी लागू किया जा सके।बैठक में जल जीवन मिशन, नल-जल योजना, बाल सक्षम नीति, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार, उद्योग आधारित प्रशिक्षण, श्रमिक हितों की सुरक्षा, नगर विकास योजना, रेलवे परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, अन्न भंडारण योजना तथा पीएम गति शक्ति योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जिले के विकास को नई गति मिल सके ।

एक नजर

आदतन नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त

बलौदाबाजार, 1 जुलाई। बैठक में सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिये नियमों का सखूती से पालन, ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपाय, जागरूकता अभियान पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा की ऐसे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालक जो आदतन नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा जिनका लाइसेंस 3 बार निलंबित हो गये हैं उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा लगातार जांच एवं चलानी कार्यवाही करें। इसके साथ ही स्कूल,कॉलेज एवं अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजण करें। उन्होंने एनएच एवं राज्य मार्गो में स्थित ब्लैक स्पॉट पर जरुरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने कहा। इसीतरह निर्माणाधीन सड़क एवं पुलियों को शीघ्र पूरा करने और निर्माण स्थल पर रेडियम पट्टी लगाने के भी निर्देश दिये। ओवर लोडिंग भारी वाहनो पर कार्यवाही हेतु खनिज एवं पुलिस विभाग को संयुक्त जांच अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।बैठक में सड़क दुर्घटना में पीड़ित का जान बचाने में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राहवीरो का सम्मान करने पर बल दिया गया। बैठक में बैठक में डीएफओ गणवीर धम्मशील,सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता,एआर टंडन, निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित एसडीएम,जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मोहड में निषाद समाज सामाजिक भवन का महापौर ने किया लोकार्पण

राजनांदगांव 1 जुलाई।(तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नगर निगम द्वारा वार्ड नं. 49 के मोहड में विधायक निधि अंतर्गत 10.00 लाख रूपये की लागत से निषाद समाज सामाजिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसका महापौर श्री मधुसूदन यादव ने एक संक्षिप्त एवं गरिमामय आयोजन में सामाजिक बुधओं की उपस्थिति में फीता काटकर पट्टीका का अनावरण कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद श्री संजय रजक सहित निषाद समाज के अध्यक्ष श्री गणेश सातर, उपाध्यक्ष श्री भुवन निषाद, सचिव श्री दिलहरण निषाद, कोषाध्यक्ष श्री हेमनाथ निषाद विशेष रूप से उपस्थित थे। लोकार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में महापौर श्री यादव ने समाज को बधाई देते हुए कहा कि, सामाजिक बंधुओं की मांग पर विधायक निधि से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। भवन निर्माण होने से अब समाज के लोगों को सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के लिये एक उचित स्थान मिल गया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक डॉ. रमन सिंह एंव सांसद श्री संतोष पाण्डे शहर विकास में अपनी निधि सहृदयता से देते है, समाज की प्रगति के लिए उनके द्वारा हर संभव मदद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भवन बनने से समाज का विकास नहीं होता वरन एकजूट होकर समाज के लोगों के हित में कार्य करने से, समाज के बच्चों को शिक्षित करने से समाज का विकास होता है। भवन में पानी की सुविधा के लिए जल्द टंकी लगाया जायेगा, इसके अलावा समाज को आवश्यकता अनुसार इसी प्रकार का सहयोग समय समय पर किया जायेगा। कार्यक्रम के पूर्व में समाज के पदाधिकारियो ने महापौर का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तत्पश्चात पूजा अर्चनाकर सामुदायिक भवन का महापौर ने विधिवत लोकापर्ण किया। इस अवसर पर निषाद समाज के लोग उपस्थित थे।

दीवान झीटिया में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ

राजनांदगांव 1 जुलाई।(तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जिले के ग्राम दीवान झीटिया स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार, 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी कुशल सिंह राजपूत ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई तथा ग्रामीणों से अपने सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रत्येक बच्चे तक यह जीवनरक्षक खुराक पहुंचाना आवश्यक है। ग्राम दीवान झीटिया के उप स्वास्थ्य केंद्र में 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ समाजसेवी कुशल सिंह राजपूत ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अभिभावकों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक बच्चे को समय पर पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य का संकल्प है।उन्होंने कहा कि ÷दो बूंद जिंदगी के नाम÷ केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर बच्चे के स्वस्थ जीवन की गारंटी है। सरकार द्वारा संचालित यह महत्वपूर्ण अभियान देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने आसपास के सभी बच्चों को भी पोलियो की खुराक दिलाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा परिवार, गाँव, समाज और देश हमेशा के लिए पोलियो मुक्त बना रहे। कुशल सिंह राजपूत ने कहा कि विगत कई वर्षों से देश और गाँव पोलियो मुक्त हैं, लेकिन इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना बेहद आवश्यक है। थोड़ी-सी लापरवाही भी भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकती है।

सुपोषित बचपन अभियान में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

- छूटे हुए हितग्राहियों का अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश

बलौदाबाजार 1 जुलाई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को समय -सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने हाल ही में शुरू हुए सुपोषित बचपन अभियान अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के कुपोषित बच्चों को पोषक लड्डू खिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबधित पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को अभियान की सतत मॉनिटरिंग करने तथा लड्डू निर्माण से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक सप्लाई और कार्यकर्त्ता द्वारा बच्चों को खिलाने तक पूरा रिकार्ड रखने के निर्देश दिये। इसीतरह गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती एवं मेडिकल चेक नजदीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र में कराने समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने खरीफ सीजन में खाद -बीज की उपलब्धता एवं केसीसी ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए किसानों को शासन के निर्देशानुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने नई समितियो में भी खाद -बीज वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने छूटे हुए किसानों का एग्रीस्टेक में पंजीयन के लिये कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियो को जरुरी समन्वय करने कहा।

कलेक्टर श्री शर्मा ने आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए अब तक छूटे हुए हितग्राहियों का कार्ड बनाने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रति सप्ताह 5000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने कहा। कलेक्टर ने मिशन उत्कर्ष अंतर्गत डीएमएफ मद से 464 शिक्षकों की अस्थई व्यवस्था करने तथा मासिक टेस्ट, ऑनलाइन पढ़ाई आदि के बेहतर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिये।

इस दौरान राजस्व प्रकरण,राजस्व कोर्ट केस, स्वामित्व योजना,पीएम आवास ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री जानदर्शन,सीएम हेल्पलाइन, सीपी ग्राम्स, सड़क एवं पुल -पुलिया निर्माण, समय -सीमा के आवेदन आदि पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में डीएफओ गणवीर धम्मशील,सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता,एआर टंडन, निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित एसडीएम,जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में करें : कलेक्टर

- - कृषि चौपाल का आयोजन कर किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के दिए निर्देश
- सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने कहा
- एचपीवी वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

राजनांदगांव 1 जुलाई। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त आवेदनों, जन शिकायतों, शासकीय योजनाओं तथा सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों तथा लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ गुणवत्तापूर्वक निराकरण करें। इसके लिए लगातार ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने कहा। कलेक्टर ने विधानसभा सत्र से संबंधित के प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिले में वृहद स्तर पर पौधरोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा, पीजीएन, पीजी पोर्टल एवं जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।

कलेक्टर ने खरीफ सीजन में खाद-बीज वितरण एवं भण्डारण और खेती-किसानी के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि शासन ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रूपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा। जिससे किसानों को कम लागत में अधिक आमदनी मिल सके। उन्होंने सभी ग्रामों में कृषि चौपाल का आयोजन कर अधिक से अधिक किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। जिले के 1 लाख 44 हजार 572 किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन पूर्ण हो चुका है। शेष किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए और इस कार्य को तेज गति से करने के निर्देश दिए। उनकी सोनोग्राफी, स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाईयों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं से प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी मोबाईल के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एचपीवी वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। जिले में 3 हजार 800 किशोरी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाया जा चुका है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को स्कूलों का रोस्टर बनाकर एचपीवी वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक माह में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना आम नागरिकों के बिजली व्यय को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जिले में अब तक 3 हजार 620 हितग्राहियों द्वारा सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। जिससे हितग्राही स्वयं ऊर्जादाता बन चुके हैं। नागरिकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जिले के अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को हितग्राहियों की चिन्हांकन कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। स्वनिधि योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के 4563 हितग्राहियों को अब तक ऋण का वितरण किया जा चुका है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोराम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

संत कबीर साहेब का प्रगट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

सिमगा 1 जुलाई। बलौदा बाजार जिले के सिमगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम नवागांव में सोमवार को संत कबीर साहेब का प्रगट उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भजन-कीर्तन एवं सत्संग के साथ हुआ, जिसमें कबीर साहेब के उपदेशों और मानवता, समानता तथा सद्भाव के संदेश पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात श्रद्धापूर्वक संत कबीर साहेब की चौका आरती संपन्न की गई। आरती के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। चौका आरती के बाद भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। आयोजन समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन कबीर साहेब के बताए सत्य, प्रेम, सद्भाव और मानव सेवा के मार्ग पर चलने के संकल्प के साथ हुआ।

सहकारी समितियों में सहकारी सप्ताह का आयोजन

सिमगा 1 जुलाई। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिमगा पंजीयन क्रमांक 1509 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक देश भर की सहकारी समितियां में सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है सहकारी सप्ताह का शुभारंभ करते हुए आज सहकारी समिति सिमगा में अध्यक्ष छोटे लाल यादव द्वारा सहकारिता ध्वज का ध्वजारोहणकर सहकारी सप्ताह का शुभारंभ किया गया समिति अध्यक्ष ने किसान भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा

सहकारिता की भावना को सशक्त बनाते हुए समृद्ध किसान सशक्त समिति एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्पों को साकार किया है किसान भाइयों को समय में समितियां से खाद बीज एवं ऋण आसानी से उपलब्ध हो उसके लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है किसान भाई अपनी उपज धान मक्का एवं दलहन किस्म के फसल सरकारी समर्थन मूल्य में समिति में बेचकर समृद्ध बना रहा है अध्यक्ष ने सभी किसान भाइयों को सहकारिता दिवस का बधाई दिया इस कार्यक्रम में अध्यक्ष छोटेलाल यादव सांसद प्रतिनिधि नीरज शर्मा समिति प्रभारी राजकुमार कोसले लखन यदू सोहन साहू पिकेसवर सोनकर ताराचंद साहू अवध राम यादव दलपत सोनकर गोपाल सोनकर गणेश सोनकर लक्ष्मण रजक रश्मि भट कुमकुम देवांगन अमित भट्ट सहित समिति कर्मचारी सम्मिलित हुए।

कलेक्टर जनदर्शन में दिव्यांग बालिका को मिली व्हीलचेयर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार 1 जुलाई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को जनदर्शन में दिव्यांग बालिका ईशु पटेल को व्हील चेयर प्रदान किया। सिमगा विकासखंड के ग्राम सकरी निवासी दिव्यांग बालिका ईशु पटेल की माताजी अपनी पुत्री की समस्या लेकर जनदर्शन में पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बताया कि उनकी सात वर्षीय पुत्री दिव्यांग होने के कारण चलने-फिरने में अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रही है, जिससे दैनिक जीवन के सामान्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।कलेक्टर श्री शर्मा ने बालिका की समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विभाग द्वारा त्वरित पहल करते हुए बालिका को मौके पर ही व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। व्हीलचेयर मिलने से बालिका एवं उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है। बालिका की माताजी ने जिला प्रशासन के त्वरित एवं संवेदनशील प्रयासों के लिए कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा तथा शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी पुत्री को आने-जाने में काफी सुविधा होगी और उसका दैनिक जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सहज हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आमजन अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

सिमगा 1 जुलाई(तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। सिमगा नगर की धरा आज फिर से पवित्र हो गई महामुनी राज श्री 108 मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्यमुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज एलक श्री 108 स्वागत सागर जी महाराज एलक श्री 108 धैर्य सागर जी महाराज का जैन मुनियों का सिमगा के आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर मे वर्तमान मे विराज मान है आपके सानिध्य में धर्म की गंगा बह रही है जैन समाज एवं नगर के अन्य समाज के लोग भी इस धर्म गंगा में अपनी जिज्ञासा एवं धर्म की इस महामुनि के शिष्यों से धर्म लाभ ले रहे हैं।

आयोग ने उपभोक्ता को नया वाहन अथवा उसका वर्तमान मूल्य देने आदेश किया पारित

बलौदाबाजार, 1 जुलाई। कंपनी द्वारा परिवादी को अमानक स्तर का वाहन दिये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकारगण को सेवा में कमी का दोषी माना। परिवादी को प्रश्ननाधीन वाहन का वर्तमान मूल्य अथवा उसी मॉडल का दूसरा नया वाहन प्रदाय किये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 20000 तथा वाद-व्यय हेतु 5000 रुपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी रघुवेंद्र डोंगरे ने विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 जायका ऑटोमोबाइल, भाटापारा रोड बलौदाबाजार से टाटा कंपनी का एकसना योद्धा वाहन क्रय किया था। क्रय दिनांक से एक सप्ताह के भीतर बहाना कर विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 ने वाहन को शो रूम में मंगाकर उपभोक्ता की बिना अनुमति के चेसिस बदलकर दूसरा चेसिस लगा दिया। उपरांत वाहन में अनेक प्रकार की खराबी आना शुरू हो गया और वाहन अचानक बंद हो गया। विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 के मैकेनिक से भी चालू नहीं हुआ विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 द्वारा नया वाहन न देकर रंग रोगन कर अन्य वाहन परिवादी को विक्रय किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेज एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि दस्तावेजों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वाहन खरीदने के एक सप्ताह बाद चेसिस को बदला गया है।

दो पुलिस अफसरों को रिटायर होने पर दी विदाई

बलौदाबाजार 1 जुलाई। जिला पुलिस बलौदाबाजार-भाटापारा में लंबे समय तक अपनी निष्ठावान और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले दो पुलिस अधिकारियों का आज दिनांक 30.06.2026 को सेवाकाल पूर्ण होने पर भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) श्री प्रेमलाल साहू और प्रधान आरक्षक 95 श्री प्रेमशंकर सिंह को उनकी दीर्घकालीन एवं सराहनीय सेवाओं के लिए भावभीनी विदाई दी गई।

प्रारूप - एक
नाम परिवर्तन सूचना

नाबालिग पुत्री के नाम परिवर्तन के मामले में अभिभावक / पालक प्रभु लाल यादव पिता लखन लाल यादव जाति - रावत निवासी ग्राम डांगनबाय तहसील छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ राज्य में अपने नाबालिग पुत्री का नाम (पुराना नाम) कु. दालेश्वरी यादव पिता प्रभु लाल यादव से बदल कर (नया नाम) ढालेश्वरी यादव पिता प्रभु लाल यादव रख लिया है।

हस्ताक्षर
प्रभु लाल यादव
माता/ पिता/ पालक

न्यायालय नायब तहसीलदार लाल बहादुर नगर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202606095000035

विषय:-ब-121
मामले की श्रेणी:- राजस्व
सनः- 2025-2026
घोरतलाव प.ह.न. 00003 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार -डाकेश कुमार कलार,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक डाकेश कुमार कलार पिता परसराम कलार जाति कलार, निवासी ग्राम घोरतलाव तहसील लाल बहादुर नगर जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि, आवेदक की माता प्रमिला बाई पति परसराम जाति कलार की मृत्यु 07.05.1998 को स्थान बागनदी में हुआ है, जो कि भूलवश ग्राम पंचायत बागनदी में संधारित मृत्यु पंजी/रजिस्ट्रार में दर्ज नही हो पाया है। आवेदक की माता प्रमिला बाई पति परसराम जाति कलार की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत बागनदी में मृत्यु पंजी में दर्ज करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है। अतः ग्राम पंचायत बागनदी में मृत्यु पंजी में दर्ज करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा आपत्ति पेश करना हो तो वह स्वयं या अपने अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2026 तक या उसके पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20/06/2026 को जारी किया जाता है।

मुहर

नायब तहसीलदार
लाल बहादुर नगर

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

(प्रथम आमंत्रण)

दिनांक 25.06.2026

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा 'डी' एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों के लिये आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.07.2026 तक है।

एन.आई.टी क्र/ निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
NIT NO.133 Tender No.194251	लोक निर्माण विभाग संभाग बलौदाबाजार अंतर्गत उपसंभाग बलौदाबाजार, कसडोल एवं भाटापारा हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 20.00 लाख
NIT NO.134 Tender No.194252	लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी अंतर्गत उपसंभाग धमतरी हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 11.00 लाख
NIT NO.135 Tender No.194253	लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी अंतर्गत उपसंभाग कुरुद हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 11.00 लाख
NIT NO.136 Tender No.194254	लोक निर्माण विभाग संभाग महासमुंद अंतर्गत उपसंभाग क्र. 1 एवं क्र. 2 हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 25.00 लाख
NIT NO.137 Tender No.194255	लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी अंतर्गत उपसंभाग नगरी हेतु अंतर्गत पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 11.00 लाख
NIT NO.138 Tender No.194256	लोक निर्माण विभाग संभाग गरियाबंद अंतर्गत उपसंभाग क्र. 1, क्र. 2 (देवभोग) एवं राजिम हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 30.00 लाख
NIT NO.139 Tender No.194291	लोक निर्माण विभाग संभाग महासमुंद अंतर्गत उपसंभाग क्र. 1 एवं क्र. 2 हेतु पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	रू. 15.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र, बिड केपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, एवं निविदाकारो द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख का लिफाफा में निविदाकारो का मोबाईल न. एवं इमेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि., रायपुर मण्डल क्र. 2 (छ.ग.)

जी-262701782/5

एक नजर

विप्र समाज की बैठक में आठ प्रस्ताव पास

रायपुर 1 जुलाई। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के प्रबंध कार्यकारिणी एवं कार्यकारिणी की जिला स्तरीय बैठक बेमेरा में संपन्न हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललित मिश्रा की अध्यक्षता एवं आचार्य बलदेव शास्त्री प्रदेश सचिव विकास घर दीवान, राजेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष डॉ शिरीष शर्मा, संभागीय महासचिव चंद्रिका प्रसाद शर्मा, शेषनारायण तिवारी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। प्रारंभ में समाज के जिला अध्यक्ष डॉ शिरीष शर्मा ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण प्रस्तुत किया उन्होंने जिला में चार ब्लॉक 9 तहसील एक नगर पालिका 7 नगर पंचायत तथा तीन विधानसभा में सामाजिक संगठन की प्रगति को प्रतिपादित किया। प्रदेश सचिव विकास घर दीवान ने 90 विधानसभा में समाज का सशक्त सामाजिक संगठन तथा प्रांत व्यापी सामाजिक जनगणना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहयोग के लिए निर्धन सहायता कोश की आवश्यकता पर बल दिया।

अष्टविनायक रियल्टीज् का आवास मेला तीन से

रायपुर 1 जुलाई। रायपुर के प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी और डेवलपर 'अष्टविनायक रियल्टीज्' और , 'अभिनव बिल्डर्स' शहरवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। 3, 4 और 5 जुलाई 2026 को, रायपुर के मोवा, दलदल सिवनी में स्थित उनके बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट 'अभिनव सिटी' में एक भव्य 'आवास मेला' आयोजित किया जा रहा है। प्रकृति के बीच एक नए युग की कम्युनिटी की परिकल्पना पर आधारित यह प्रोजेक्ट लग्ज़री, सुविधा और शांति का बेहतरीन मेल है। इस तीन -दिवसीय आवास मेले में ग्राहकों को उनकी आवश्यकता और बजट के अनुसार विविध विकल्प मिलेंगे: ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार गार्डन प्लॉट्स, गार्डन फेसिंग प्लॉट्स, कॉर्नर प्लॉट्स या गार्डन फेसिंग और कॉर्नर प्लॉट्स का चयन कर सकते हैं। 2 और 3 बीएचके लग्ज़री अपार्टमेंट्स: आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखकर बनाए गए इन अपार्टमेंट्स में 2 बीएचके (1066 वर्ग फुट और 1125 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप एरिया) रेरा कारपेट एरिया 672 वर्ग फुट और 714 वर्ग फुट और 3 बीएचके (1317 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप एरिया) रेरा कारपेट एरिया 959 वर्ग फुट के शानदार विकल्प मौजूद हैं।

हिन्दुस्तान जिंक ने 60 साल पूरे किये

रायपुर, 1 जुलाई। विश्व की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादक और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सिल्वर उत्पादकों में से एक वेदांता रूप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी 60वीं वार्षिक आम बैठक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संचालन के छह दशक पूरे होने पर हिंदुस्तान जिंक 2.0 विजन को और मजबूत किया, जो भविष्य के लिए तैयार मल्टी-मेटल एंटरप्राइज बनने की दिशा में एक निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया, इसमें खनन किए गए मेटल का प्रोडक्शन 1.1 मिलियन टन से अधिक रहा जो अब तक का सबसे अधिक है, और रिफाइंड मेटल का आउटपुट दूसरा सबसे अच्छा रहा, साथ ही वैश्विक स्तर पर लागत के मामले में सबसे कम लागत वाली कंपनियों में से एक बनी रही। वित्त वर्ष 26 हिंदुस्तान जिंक के सबसे मजबूत वित्तीय वर्षों में से एक रहा, जिसमें रिकॉर्ड रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया। ऑपरेशनल एक्सीलेंस और अनुशासित लागत प्रबंधन के कारण एबिटा मार्जिन 50 प्रतिशत से अधिक रहा, जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है।

शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक शिक्षकों को मिलेगी पुनर्नियुक्ति

रायपुर 1 जुलाई। शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है।लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

खेल प्रतिभाओं को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार : साय

रायपुर 1 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव सहित समिति के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। इनमें 20 अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं।

बैठक में अनुमोदित 156 खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ होगी। राज्य के खिलाड़ी लंबे समय से इस सूची की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद खिलाड़ियों का यह इंतजार जल्द समाप्त हो जाएगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पात्रता के अनुरूप उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों का अनुभव और उपलब्धियां प्रदेश की नई खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, इसलिए उनकी सेवाओं का उपयोग खेल प्रशिक्षण, प्रतिभा संवर्धन और खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में भी किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत खेल व्यवस्था विकसित करना है, जहां गांव से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाओं की समय रहते पहचान हो, उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से खेल गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा खेल प्रतिभाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल अधोसंरचना के विस्तार, आधुनिक सुविधाओं के विकास तथा नई खेल अकादमियों की स्थापना की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना है जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आज चयनित खिलाड़ी भविष्य में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए पूर्व में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण और निर्धारित मानकों के आधार पर 156 खिलाड़ियों को पात्र पाया गया।

बैठक में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम उपस्थित थीं।

उपरवारा की महिलाओं को मिला स्वरोजगार का नया अवसर

रायपुर 1 जुलाई। युवा रायपुर के एंटरप्रेन्योरशिप वर्टिकल एवं आईटीएम यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में उपरवारा गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित 10 दिवसीय टिफिन सर्विस उद्यमता प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं सफल महिला उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करना था। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को आधुनिक एवं बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना सिखाया गया। इसमें कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज़ व्यंजन, आधुनिक भारतीय व्यंजन, स्नैक्स, प्रिज़ेंमेंट्स, बेवरेजेस तथा मॉकटेल्स बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सिर्फ दस दिनों में प्रतिभागियों ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई। महिलाओं ने स्वयं विभिन्न व्यंजन तैयार किए और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी उद्यमशीलता की शुरुआत भी की। इस अनुभव से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें स्वरोजगार का एक नया मार्ग मिला। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने स्वयं का टिफिन एवं फूड सर्विस व्यवसाय शुरू करने की उत्सुकता व्यक्त की तथा भविष्य में भी वाईआई रायपुर एवं आईटीएम यूनिवर्सिटी से मार्गदर्शन एवं सहयोग की अपेक्षा जताई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता में डॉ. लक्ष्मी मूर्ति, प्रो वाइस चांसलर, श्री अनीश बनर्जी, प्राचार्य, स्कूल ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट (साझेदार), डॉ. अमेया जानी, शेफ ट्रेनर तथा सुश्री वैष्णवी शिकदार, जूनियर ट्रेनर एवं एसएचटीएम की तृतीय सेमेस्टर की छात्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समापन समारोह में पंकज सोमानी, चेयर, एंटरप्रेन्योरशिप वर्टिकल, वाईआई रायपुर एवं कविता पसारी, को-चेयर ने प्रतिभागियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया तथा भविष्य में भी हर संभव सहयोग एवं मार्गदर्शन का आश्वासन दिया।

दिव्यांग बच्चों के विकास एवं पुनर्वास पर एक दिवसीय सेमिनार 4 जुलाई को

रायपुर 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद, रायपुर द्वारा दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास, शिक्षा एवं पुनर्वास को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 4 जुलाई 2026, शनिवार को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक वीमतरा भवन (स्वदेशी भवन के पास), न्यू शांति नगर, रायपुर में आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव चंद्रेश शाह ने बताया कि सेमिनार में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों, उनके विकास, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित मानकों, अवसरों एवं समावेशी शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावक एवं दिव्यांग बच्चों के हित में कार्य करने वाले संगठन भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेमीनार में इन्मु के डॉ. आलोक उपाध्याय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के श्री योगेंद्र पाण्डे, रिटायर्ड आईपीएस सज्जाद नकवी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, अधिवक्ता सुगंधा जैन, डाइटिशियन डॉ. सारिका श्रीवास्तव आमंत्रित विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहेंगे।

नकटी में मकानों पर बुलडोजर चलाना अमानवीय: दीपक बैज

रायपुर 1 जुलाई । राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अमूमन मानवीय आधार पर बारिश के समय विस्थापन की कार्यवाही नहीं की जाती है, यह छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून मानसून आने का समय माना जाता है। इस समय के बाद राज्य के जमीनों का सीमांकन भी नहीं किया जाता है। नकटी गांव में तोड़-फोड़ की कार्यवाही 29 जून को की गयी है, जो पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी प्रक्रिया है। इस कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट भी जायेंगे। किसी भी विस्थापन की कार्यवाही के पहले व्यवस्थापन होना था, सरकार ने बिना व्यवस्थापन कार्य को पूरा किये वहां पर रह रहे लोगो को समान हटाने का अवसर दिये बिना तोड़-फोड़ किया, उनके घरो में बुलडोजर चलवाया।

सरकार ने प्रभावितों को जो अस्थायी आवंटन पत्र दिया है उसके अनुसार 5.50 लाख, 8.50 लाख दो श्रेणी के मकान दिया है। इसका राशि का भुगतान कौन करेगा? इसको पूरा निःशुल्क क्यों नहीं किया गया?

हम, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से भी आग्रह करते है कि गरीबों की आह लेकर बनाई जा रही इस कॉलोनी में आवास लेने से मना करें। सरकार के पास नये रायपुर में हजारों एकड़ खाली जमीने है। सरकार विभिन्न संस्थाओं कंपनियों को मुफ्त में 1 रू. फ्रि में जमीने देती है। वहां पर विधायक कालोनी क्यों नहीं बनाते है? सरकार अपनी गलती माने तोड़े गये मकानों को वहीं पर फ्रि से बनाकर दिया जाये। मकानों को तोड़ने पर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे।

रेट फ्रिक्स नहीं हो पा रहा इसलिए तबादला नीति तय नहीं हो पा रही: कांग्रेस

रायपुर 1 जुलाई। भाजपा सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए अभी तक तबादला नीति नहीं तय होने पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विभिन्न शासकीय विभागों में कर्मचारियों के तबादला का रेट मंत्री अभी फ्रिक्स नहीं कर पाये है, इसीलिए अभी तक सरकार ने तबादला नीति घोषित नहीं किया। जबकि परंपरा के अनुसार अभी तक तबादले शुरू हो जाने चाहिए थे। दाई सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों को उद्योग बना दिया गया है। भाजपा का छोटा-बड़ा नेता, मंत्री, उनके स्टाफ्फ के लोग तबादला कराने और रूकवाने के नाम पर वसूली अभियान चलाते है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले वर्ष भी तबादला नीति में शिक्षा, पुलिस, परिवहन, खनिज, वाणिज्य पंजीयन विभाग कर्मचारियों को तबादला नीति से बाहर रखा गया, जिससे 3.50 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए थे। बाद में टुकड़ों में तबादला सूची निकाल कर फ्रि रोकने के नाम पर बड़ी वसूली साल भर की गयी थी।

आईटीएम यूनिवर्सिटी में प्रवेश जारी

रायपुर,1 जुलाई। आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा छत्तीसगढ़ की नंबर-1 यूनिवर्सिटी का स्थान प्राप्त करने वाली आईटीएम यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, इंटर्नशिप और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट सहायता प्रदान करती है। यहां के विद्यार्थियों का चयन आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और आईटीसी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में हुआ है। यूनिवर्सिटी के प्रत्येक डिग्री कार्यक्रम में तीन से छह महीने की अनिवार्य औद्योगिक इंटर्नशिप शामिल है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक अनुभव मिलता है और वे रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाते हैं। यूनिवर्सिटी के कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्लेसमेंट हासिल किए हैं। खुशबू तुमाए, दीपिका साहू और आर्यन शर्मा को चयन आईडीबीआई बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर हुआ है। वहीं, होटल प्रबंधन के विद्यार्थियों को रैडिसन हयात, दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय होटल समूहों में भी रोजगार मिला है। यूनिवर्सिटी हर वर्ष 70 से अधिक कंपनियों की भागीदारी के साथ कैंपस रोजगार मेले का आयोजन करती है, जिससे रायपुर, भिलाई और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं।

भाजपा महिला मोर्चा भी होगा डिजिटल

रायपुर 1 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा है कि भाजपा का 'डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम' कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक, पार्टी की विचारधारा, इतिहास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष प्रशिक्षण अभियान है। श्रीमती अवस्थी ने कहा कि इस अभियान को महिला कार्यकर्ताओं के बीच बूथ स्तर तक पहुँचाने महिला मोर्चा ने तैयारी पूरी कर ली है।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अवस्थी ने डिजिटल प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आधुनिक युग में डिजिटल होना आवश्यक है क्योंकि आज के दौर में त्वरित जानकारियाँ, मुद्दे और विषय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होते हैं, अतः भाजपा महिला मोर्चा को डिजिटल क्षेत्र में पूर्ण प्रशिक्षित होना अनिवार्य है ताकि वे बेहतर तरीके से डिजिटल क्षेत्र के कार्य करने में सक्षम हो सकें। श्रीमती अवस्थी ने इस कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण भाजपा के आधिकारिक सरल ऐप के माध्यम से डिजिटली प्रदान किया जाता है। इसका आधारभूत मुख्य पाठ्यक्रम कार्यकर्ताओं को चार प्रमुख मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है, जिसके तहत भाजपा की विचारधारा और पार्टी का इतिहास , नेतृत्व और पंचनिष्ठा , नमो ऐप का उपयोग एवं साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की जन-कल्याणकारी विकास योजनाओं को डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अवस्थी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में डिजिटल प्रशिक्षण की प्रक्रिया विस्तार से बताई जाएगी। कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल ऐप पर वीडियो और अध्ययन सामग्री के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के 104.54 करोड़ जारी

रायपुर 1 जुलाई। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। श्री साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं।

दिव्यांग बच्चों संग थौरानी ने मनाया जन्मदिन

रायपुर 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी का जन्मदिन चेम्बर भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में बेहद धूमधाम, उल्लास और सेवाभावी संकल्पों के साथ मनाया गया। व्यापारी वर्ग की प्रखर आवाज सतीश थौरानी के जन्मदिवस को चेम्बर ने सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में मनाया, जिसमें प्रदेशभर के व्यापारी, पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी चेम्बर भवन पहुंचे, उपस्थित व्यापारियों और पदाधिकारियों ने ढोल-नगाड़ों की थाप, आतिशबाजी और जोरदार पुष्पवर्षा के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया। पूरे परिसर में जश्न का माहौल था और व्यापारियों ने उन्हें फूलों के बड़े हार और बुके भेंट कर दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दीं।

तत्पश्चात इस पावन अवसर पर चेम्बर ने सामाजिक सरोकार की एक बड़ी मिसाल पेश की। रामकृष्ण केयर अस्पताल के सौजन्य से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के 1000 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच किया जाएगा, जिसे चेम्बर के इतिहास में एक बेहद सराहनीय कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही, अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी जी के जन्मदिन को वास्तव में सेवा और संवेदना का प्रतीक बनाते हुए अपंग दिव्यांग पब्लिक स्कूल के विशेष एवं जरूरतमंद बच्चों के साथ खुशियां बांटी गईं।

बदलाव महंगाई की मार झेल रहे लोगों को बिजली का झटका

बिजली उपभोक्ताओं को आज से प्रति यूनिट देने होंगे 30 से 50 पैसे ज्यादा

रायपुर 1 जुलाई। छत्तीसगढ़ में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से बिजली का झटका लगने वाला है. छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं. अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे. पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थी.

पिछले साल घरेलू बिजली में जहां 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई थी, वह इस बार 30 से 50 पैसे बढ़ गई है. गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है. कृषि पम्पों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किये गए हैं. इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है.

बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा. इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है.

कबीर जयंती महोत्सव के दिन मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी. इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफी नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे.

सेवानिवृत्त शिक्षिका को दी गई विदाई

रायपुर 1 जुलाई। विकासखंड साजा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवोड़ में सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित शिक्षकों के सम्मान में आयोजित गरिमामय विदाई समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं ग्रामवासियों ने शिक्षकों का आत्मीय सम्मान करते हुए उनके योगदान को भावभीनी श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ याद किया। समारोह के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा चौबे के सेवानिवृत्ति अवसर पर उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनके लंबे, समर्पित एवं अनुकरणीय शैक्षणिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी ने कहा कि विदाई शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसके पीछे जीवनभर का समर्पण, संघर्ष, अनुशासन, सेवा और अनगिनत यादें जुड़ी होती हैं।

कौशल किशोर मिश्र प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी की ओर से तरुण छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस टॉवर, प्रेस काम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादक- कौशल किशोर मिश्र, पंजी. क्रं. 45088/85 डाक पं.छ.ग./रायपुर संभाग/33/2024-26